



देश की आत्मा आदिवासियों ने सुरक्षित रखी: मोहन भागवत

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि विदेशी आक्रमणों और कठिनाइयों के बावजूद आदिवासी समुदायों तथा अनुसूचित जातियों ने देश की पहचान और आत्मा को सहेजकर रखा। वह यहां कर्मयोगी पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे।

भागवत ने कहा, “मानव जीवन दुनिया को कुछ वापस देना होता है, क्योंकि हम सभी एक महान परिवार का हिस्सा हैं। एक व्यक्ति समाज की बेहतरी के लिए काम करता है, उपकार के तौर पर नहीं, बल्कि कर्तव्य के रूप में। दूसरों की सेवा करके हम अपना विकास करते हैं। दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करके हम स्वयं को उन्नत करते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। यह सिद्धांत इस भारतीय भूमि का मूल मूल्य है, जिसे आमतौर पर हिंदू समाज के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, “यह समाज का वह चिरस्थायी लोकाचार है, जो हजारों वर्षों से कायम है। विभिन्न कारणों से, आंशिक रूप से हमारी उदासीनता के कारण और आंशिक रूप से विदेशी आक्रमण के कारण, इस लोकाचार को संरक्षित करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ी।” आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने देखा



कि यही लोकाचार, समाज का यही मूल्य इसकी आत्मा है और इसे बनाए रखने की कुंजी है, इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने इस आत्मा को संरक्षित करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया और इस कारण उन लोगों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा कि हालांकि विदेशी आक्रमणों और कठिनाइयों के बावजूद आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जातियों ने देश की पहचान और उसकी आत्मा को संरक्षित रखा। भागवत ने कहा, अस्तित्व की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, आदिवासी समुदायों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूहों के बीच देश की मूल पहचान बरकरार रही। उन्होंने इन समुदायों की मुख्याधार की विकास प्रक्रिया में एकीकृत करने की आवश्यकता

पर बल दिया, साथ ही यह सुनिश्चित करने की बात कही कि उन्हें सेवाओं और सुविधाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। वैश्विक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए भागवत ने कहा कि “जिस तरह से दुनिया इस समय डाँवाडोल हो रही है, वैश्विक उथल-पुथल मची है, ऐसे में सुदृढ़ और संबल भारत ही विश्व का आधार बन सकता है।” भागवत ने कहा कि देश को न केवल अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए बल्कि विश्व को भी समर्थन देना चाहिए। उन्होंने कहा, विश्व को यह दिखना चाहिए कि देश न केवल अपनी समस्याओं का समाधान कर रहा है, बल्कि विश्व को भी इसी तरह की समस्याओं से निपटने में मदद कर रहा है।” आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समाज सेवा कोई उपकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जो स्वयं के विकास में योगदान देता है। उन्होंने कहा कि दूसरों के विकास में मदद करने से व्यक्ति का उत्थान होता है और समाज का ताना-बाना मजबूत होता है।

भागवत ने कहा कि तथाकथित शिक्षित और विकसित वर्ग समय के साथ इन समुदायों से दूर हो गए। उन्होंने इस ख़ाई को पाटने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों द्वारा संरक्षित पहचान भारतीय समाज की सच्ची पहचान का प्रतिनिधित्व करती है और इस बात पर जोर दिया कि पहचान के बिना अस्तित्व ही खतरे में होता है

विकास कार्यों का निरीक्षण करने स्कूटी में निकले डिप्टी सीएम साव



लोरमी। अक्सर राजनीति में ऊंचे पदों पर बैठे चेहरों के इर्द-गिर्द सुरक्षा का अभेद्य घेरा और सायरन बजाती गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस ‘वीआईपी दीवार’ को ढहाकर एक नई मिसाल पेश की है। आज उप मुख्यमंत्री का एक ऐसा अंदाज दिखा, जिसने यह साबित कर दिया कि वे पद से नहीं, बल्कि दिल से जमीन से जुड़े नेता हैं।

आईईडी निष्क्रिय करते समय विस्फोट से चार जवान बलिदान

कांकर। छत्तीसगढ़ के कांकर जिले में एक आईईडी विस्फोट में ‘जिला रिजर्व गाईड’ (डीआरजी) के एक अधिकारी समेत चार जवानों की मौत हो गई। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज ने बताया कि इस घटना में दल का नेतृत्व कर रहे डीआरजी के निरीक्षक सुखराम बट्टी (40), जिला बल के आरक्षक कृष्णा कुमार कोमरा (35), और बस्तर फाइटर्स के आरक्षक संजय गढ़पाले (29) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में घायल हुए बस्तर फाइटर्स के एक आरक्षक परमानंद कोराम (29) को हवाई मार्ग से रायपुर ले जाया गया था, लेकिन वहां अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।



पुलिस अधिकारियों के अनुसार छोटेबेठिया थानाक्षेत्र में कांकर-नारायणपुर जिले की सीमा के पास सुरक्षाबलों के बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने और गश्त के लिए भेजा गया था। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के आदनार गांव के जंगल में बारूदी सुरंग को निष्क्रिय करने के अभियान के दौरान दुर्घटनावश विस्फोट हो जाने से तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

उन्होंने बताया कि घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टिलिंगम ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में आत्मसमर्पण कर चुके माओवादी कैडरों से प्राप्त जानकारी तथा अन्य सूचना के आधार पर बस्तर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए सैकड़ों आईईडी को पुलिस और सुरक्षाबलों ने बरामद कर निष्क्रिय कर दिये हैं। सुंदरराज ने बताया कि शनिवार का अभियान छोटेबेठिया इलाके में माओवादियों

द्वारा छोड़ दिये गये सामानों (डंप) के बारे में मिली इसी तरह की जानकारी के बाद शुरू किया गया था उन्होंने बताया कि डीआरजी के नेतृत्व वाले इस दल में बस्तर फाइटर्स और जिला बल के जवान भी शामिल थे। महानिरीक्षक ने बताया कि अभियान के दौरान दल ने सबसे पहले एक (माओवादी) ‘डंप’ खोज निकाला और वहां से नक्सलियों का सामान बरामद किया। उन्होंने कहा कि पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे इस दल को एक और ‘डंप’ मिला, जहां जमीन के नीचे एक आईईडी छिपाकर रखा गया था। उन्होंने बताया कि जब जवान आईईडी को निष्क्रिय करने के लिए उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी वह फट गया।

कर्नाटक में सिद्धारमैया की कुर्सी पर संकट : प्रल्हाद जोशी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शनिवार को दावा किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में असमंजस बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना भी की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में भ्रम की स्थिति है। हाई कमांड ने डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा शुरू कर दी है। वे किसे मुख्यमंत्री चुनते हैं, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है और यह हमारा विषय भी नहीं है। खरगे या परमेश्वर का नाम लेना सिर्फ गुमराह करने और डीके शिवकुमार द्वारा उल्लिखित 50-50 समझौते को लेकर भ्रम पैदा करने के लिए है। ऐसा कोई समझौता हुआ है या नहीं, यह सिर्फ वे ही जानते हैं। इसका नतीजा यह है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की स्थिति झुंज आज यह संभवतः भ्रष्टाचार में नंबर एक पर है। वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं।



पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित जालसाजी और मानहानि से संबंधित मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले का स्वागत किया और इस राहत को राज्य सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक चेतावनी बताया। एक्स से बात करते हुए, खेड़ा ने सर्वोच्च न्यायालय और अपनी पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि यह आदेश कानून के शासन को मजबूत करता है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का विधि के शासन को कायम रखने के लिए धन्यवाद करता हूँ... मेरी जमानत न केवल मेरी व्यक्तिगत जीत और राहत का स्रोत है, बल्कि राज्य शक्ति का दुरुपयोग करने वालों के लिए एक चेतावनी भी है कि जब तक हम संवैधानिक लोकतंत्र बने रहेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राजनीतिक प्रतिशोध के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता। झूठ चाहे कितना भी भयानक क्यों न लगे, सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते!



आप छोड़ भाजपा में आए संदीप पाठक पर एफआईआर दर्ज

चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कुछ दिनों बाद पंजाब में उनके खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सांसद के खिलाफ मामले क्यों दर्ज किए गए हैं, सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये मामले गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। शनिवार को एफआईआर दर्ज होने की खबरों के बीच, पाठक को उनके दिल्ली स्थित आवास से निकलते हुए देखा गया। जब उनसे पूछताछ के लिए संपर्क किया गया, तो राज्यसभा सांसद अपनी कार में सवार होकर रवाना होते दिखे। सरकारी सूत्रों ने बताया, पंजाब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है क्योंकि गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस खबर के बारे में पूछे जाने पर संदीप पाठक ने मीडिया को बताया, मुझे अपने खिलाफ दर्ज किसी एफआईआर की जानकारी नहीं है।



टीवीके को 180 सीटों पर मिलेगी जीत : केए सेनगोष्टैन

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बयानबाजी तेज हो गई है। तमिलनाडु वेट्टो कडुगम (टीवीके) के कार्यकारी समिति के मुख्य समन्वयक केए सेनगोष्टैन ने शनिवार को दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य की 234 में से कम से कम 180 सीटों पर जीत हासिल करेगी। गोविन्देष्टीपालयम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेनगोष्टैन ने कहा कि टीवीके न केवल बहुमत हासिल करेगी बल्कि 180 से 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी और उसके नेता को जनता से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, जिसका उन्हें हाल के दिनों में व्यक्तिगत अनुभव भी हुआ। टीवीके प्रमुख विजय को लेकर उन्होंने कहा कि वह दूरदर्शी सोच के साथ तमिलनाडु का नेतृत्व करेंगे और 2026 का चुनाव ऐतिहासिक जीत लेकर आएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विजय ने कई चुनौतियों और विरोध के बावजूद अपनी राजनीतिक यात्रा जारी रखी है और जनता इसका जवाब 4 मई को देगी।



सुभेंदु ने संविदा कर्मियों की तैनाती पर उठाए सवाल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से ठीक पहले सियासी माहौल गरमा गया है। पिंगला और दासपुर विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना ड्यूटी के लिए संविदा और अस्थायी कर्मचारियों की तैनाती को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा उम्मीदवार सुभेंदु अधिकारी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर खतरा बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि मतगणना जैसे अत्यंत संवेदनशील कार्य में जीविका सेवक, सहायक और संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे कर्मियों को तैनात करना चिंताजनक है। ये कर्मचारी स्थायी सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं होते और उन पर राजनीतिक दबाव पड़ने की आशंका अधिक रहती है, जिससे चुनाव परिणामों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने विशेष रूप से पिंगला और दासपुर विधानसभा क्षेत्रों के जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कई संविदा कर्मियों को मतगणना और संकलन टीमों में शामिल किया गया है।



नारी शक्ति वंदन और पहाड़ का राजनीतिक भविष्य

जयसिंह रावत

उत्तराखंड के वर्तमान राजनीतिक विमर्श में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक अत्यंत जटिल और विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र ने उस राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है जिसमें महिला सशक्तिकरण के समर्थन के साथ-साथ परिसीमन के छिपे हुए खतरों पर चिंता जताई जा रही है।

एक ओर जहां महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने का ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर परिसीमन की वह अदृश्य तलवार लटक रही है जो उत्तराखंड के पर्वतीय

अस्तित्व के राजनीतिक आधार को कमजोर कर सकती है। राय का सबसे बड़ा संकट यह है कि इस आरक्षण की आड़ में होने वाले संभावित परिसीमन से पहाड़ की राजनीतिक शक्ति का केंद्र मैदानों की ओर खिसक सकता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक के साथ जुड़ा परिसीमन का फॉर्मूला उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। यदि राय की विधानसभा सीटें 70 से बढ़ाकर 105 की जाती हैं, तो जनसंख्या आधारित वितरण पहाड़ के विरुद्ध जाता दिख रहा है। अब तक सीटों के निर्धारण के लिए विचलन का एक निश्चित मानक अपनाया जाता रहा है। पूर्व में एक सीट के लिए औसतन एक लाख

की जनसंख्या का मानक रखा गया था, जिसमें 10 प्रतिशत के विचलन की अनुमति थी। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में एक लाख 10 हजार की जनसंख्या पर एक सीट और पहाड़ में 90 हजार की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हुआ था। लेकिन वर्तमान जनसंख्या अंशतुलन को देखते हुए यह 10 प्रतिशत का अंतर पहाड़ की सीटों को बचाने के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। इसी संकट को देखते हुए योत सिंह बिष्ट जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। उनकी मांग है कि उत्तराखंड



जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राय के लिए इस विचलन की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए।

यदि इस मानक को अपनाया जाता है, तो पहाड़ की कम जनसंख्या वाली सीटों को भी संवैधानिक सुरक्षा मिल सकेगी और परिसीमन के बाद भी

पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों में कटौती नहीं होगी। यह मांग केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि पहाड़ के अस्तित्व को बचाने की एक अनिवार्य शर्त बन गई है, ताकि जनसंख्या के आधार पर होने वाला सिरों का गणित पहाड़ के भूगोल को राजनीतिक रूप से बेदखल न कर दे। उत्तराखंड राय का गठन किसी सामान्य प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि पहाड़ की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया था। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यह तर्क प्रमुखता से उभरा कि परिसीमन का आधार केवल 2011 या 2027 की जनगणना को नहीं बनाया

जाना चाहिए। विपक्ष और क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना ​​है कि उत्तराखंड में भौगोलिक परिस्थितियों को प्राथमिकता मिलना अनिवार्य है। मैदान में जहाँ एक विधायक सुगमता से लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, वहीं पहाड़ में एक प्रतिनिधि को कई सौ किलोमीटर के दुर्गम और कटे-फटे भूगोल का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। यदि केवल जनसंख्या ही आधार रही, तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व सदन में अल्पमत जैसा हो जाएगा।

पहाड़ के लोगों को उनके त्याग और मजबूरी की दोहरी सजा मिल रही है। सुविधाओं के अभाव में जिस जनता को पलायन करना पड़ा, अब उसी

पलायन के कारण घटी जनसंख्या को आधार बनाकर उनसे उनकी राजनीतिक पहचान छीनी जा रही है। यह उस पर्वतीय राय की मूल अवधारणा पर प्रहार है जिसके लिए राय आंदोलन में भारी बलिदान दिए गए थे। महिला आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देना है, जो कि एक सराहनीय कदम है, लेकिन यदि इसकी आड़ में भौगोलिक प्रतिनिधित्व ही समाप्त हो जाए, तो पहाड़ की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। पहाड़ का संविदा कर्मियों के हाथ से निकल जाएगा।

छत्तीसगढ़ में आईडी ब्लास्ट, डीआरजी के तीन जवान शहीद, एक घायल

कांकेर। छत्तीसगढ़ में कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर डी माइनिंग ऑपरेशन के दौरान दृष्टछ ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की चपेट में आकर छन्नन्न के 3 जवान शहीद हो गए और एक जवान घायल हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि छोटेबेटिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक वन क्षेत्र में यह घटना हुई है। डीआरजी की एक टीम नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय करने का अभियान चला रही थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। कांकेर एसपी निखिल राखेचा ने बताया



कि कांकेर जिले के छोटेबेटिया थाना क्षेत्र के कोरोसकोड़ा इलाके में जवान सर्चिंग और डी माइनिंग के लिए निकले हुए थे। यह नारायणपुर और कांकेर का बॉर्डर इलाका है। डी मीईनिंग के दौरान आईईडी बम विस्फोट हो गया। जिसकी चपेट में आने से कांकेर छन्नन्न के तीन जवान शहीद हो गए। तीनों घायल सदस्यों को उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं स्कन ने बताया कि इस

रिंगबांध से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, अंबिकापुर निगम प्रशासन का चला बुलडोजर

सरगुजा। अंबिकापुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। जल मार्ग रोकने और बिना अनुमति के मिट्टी पाटने पर निगम ने कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन और निगम की संयुक्त टीम अतिक्रमण खाली कराने पहुंची है। करीब 57 डिस्मिल जमीन पर पाटी गड़ मिट्टी हटाने की कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि रिंगबांध पर कच्चे के आरोप लग रहे हैं। जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। प्रशासन और निगम की टीम दल बल के साथ मौके पर कार्रवाई कर रहा है। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के सामने रिंगबांध नामक जल क्षेत्र की जमीन पर मिट्टी पाटी का रही थी। जिस पर स्थानीय लोगों ने बवाल खड़ा किया था। शिकायत की गई और आरोप लगाया गया कि ये शासकीय जमीन पर जल क्षेत्र को कब्जा किया जा रहा है। दूसरे पक्ष की दलील है की वो जमीन निजी संपत्ति थी जिसे खरीदा गया है। इस बीच इस जमीन से जल क्षेत्र का मार्ग बाधित करने और नगर निगम से बिना अनुमति लिए करीब 57 डिस्मिल जमीन पर मिट्टी पाटने की कार्रवाई निगम ने की है और प्रशासन ने साथ मिलकर संयुक्त



टीम आज मौके पर मिट्टी हटाने का काम कर रही है। बड़ी बात ये हैं की इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्चा भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा। इस मामले में नगर निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने कहा कि बांध को पाटा गया था तो उसको फिर से उसके मूल रूप में लाने के लिए यहां जितना भी मिट्टी पाटा गया है, उसको आज निगम के द्वारा हटाने की कारवाई किया जा रहा है। यहां पर जिसके नाम से जमीन है वो तालाब को पाट रहे हैं। तो उस पर जांच किए थे नोटिस दिए थे और उनके द्वारा इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं लिया गया था और मूलतः तालाब ही था- डीएन कश्यप, आयुक्त नगर निगम डीएन कश्यप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। इसलिए इस मिट्टी को हटाने का काम कर रहे हैं। ये जो नगर निगम एक्ट के प्रावधान है उसके तहत नोटिस दिया गया था और जो भी मिट्टी यहां पे हटा रहे हैं उसका खर्च भी हम संबंधित व्यक्ति से वसूलेंगे।

बैंक में 1.38 करोड़ की हेराफेरी उपभोक्ताओं के सोना लेकर फरार

बिलासपुर। जिले में आईसीआईसीआई बैंक की मंगला स्थित शाखा में 1.38 करोड़ रुपये की बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में बैंक की डिप्टी ब्रांच मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने अपने पति के साथ मिलकर साजिश रची और उपभोक्ताओं के गोल्ड लोन में गिरवी रखे गए सोने को लेकर फरार हो गई। जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने ग्राहकों के एफडी और गोल्ड लोन से जुड़े खातों में गड़बड़ी करते हुए बैंक को भारी नुकसान पहुंचाया है। जब बैंक प्रबंधन ने दस्तावेजों और लॉकर की जांच की तो गोल्ड लोन के पाउच में असली सोने की जगह नकली आभूषण पाए गए, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ। इस घोटाले की जानकारी मिलते ही बैंक के ब्रांच मैनेजर ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज कर लिया है। घटना सिविल लाइन क्षेत्र के मंगला स्थित आईसीआईसीआई बैंक शाखा की है। फिलहाल सिविल लाइन पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव का सामने आया अनोखा अंदाज

लोरमी। अक्सर राजनीति में ऊंचे पदों पर बैठे चेहरों के इर्द-गिर्द सुरक्षा का अभेद्य घेरा और सामन्य बजाती गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने इस ‘वीआईपी दीवार’ को ढहाकर एक नई मिसाल पेश की है। आज उप मुख्यमंत्री का एक ऐसा अंदाज दिखा, जिसने यह साबित कर दिया कि वे पद से नहीं, बल्कि दिल से जमीन से जुड़े नेता हैं। उपमुख्यमंत्री अरुण साव औचक निरीक्षण पर निकले थे, लेकिन उनका तरीका किसी को भी चौंकाने वाला था। अपनी चमचमाती सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल को छोड़, डिप्टी सीएम ने एक आम नागरिक की तरह स्कूटी उठाई



और खुद हैंडल संभालकर गलियों में निकल पड़े। रास्ते में जो भी मिला अरुण साव ने उनसे सीधे संवाद किया। स्कूटी रोककर बुजुर्गों का हाल जाना और युवाओं से विकास कार्यों पर फीडबैक लिया। जनता के बीच

यह चर्चा का विषय है कि एक उपमुख्यमंत्री का इतना सहज और सरल होना कोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों को समय से गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

छत्तीसगढ़

तेंदूपत्ता सीजन में जंगली जानवरों का आतंक! 6 भालुओं के दल ने 2 ग्रामीणों को किया घायल

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में तेंदूपत्ता तोड़ाई शुरू होने के बाद जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 6 भालुओं ने जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर दौड़ा-दौड़ा कर हमला कर दिया। दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिन्हें अब बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, घटना सड़क पारसोली वन परिक्षेत्र के हरदी गांव की है। ग्रामीणों का समूह तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए पहुंचे थे। लेकिन यहां 6 भालुओं के समूह ने ग्रामीणों पर अचानक हमला कर दिया। सभी अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे। भालुओं ने दौड़ा-दौड़ाकर



हमला किया। इस दौरान 2 ग्रामीण बुरी तरह से जख्मी हो गए।

दोनों ग्रामीण किसी तरह अपनी जान बचाकर परिजनों को सूचना दी। घायलों को प्राथमिक

इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, अब उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संध्या नायक को वीडियो कॉल कर दी बधाई, कक्षा 10वीं में किया स्टेट टॉप

महासमुंद। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं कक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। हाई स्कूल में तीन छात्रों ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। जिसमें पहला स्थान संध्या नायक का है। संध्या के अलावा, परी रानी प्रधान और अंशुल शर्मा ने 99.00 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं। संध्या नायक को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने फोन पर वीडियो कॉल करके बधाई दी। ओपी चौधरी ने संध्या नायक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए पूरे परिवार को बधाई दी। वहीं, संध्या नायक ने ओपी चौधरी को अपना आइडल मानते हुए कहा कि वह सिविल सर्विसेस की तैयारी करना चाहती हैं। जिस पर चौधरी ने संध्या नायक के घर आकर उन्हें मार्गदर्शन देने का वादा किया है। बता दें कि संध्या नायक और परी रानी प्रधान महासमुंद जिले से हैं।



अंशुल शर्मा मुंगेली जिले से हैं। इन तीनों ने 594 अंक प्राप्त किए हैं। रिया केशरवानी और रानू सिद्धिमयी साहू ने 98.83 फीसदी अंक प्राप्त किए। रितुका प्रधान, दीपांशी बौड़ और नंदिता देवांगन ने भी 98.83

रिया केशरवानी के घर पहुंचे कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा मीठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं



कवर्धा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कवर्धा की छात्रा रिया केशरवानी ने पूरे प्रदेश की मेरिट सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। रिया ने 600 में से 593 अंक प्राप्त कर 98.83 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं, जो उनकी

माइंस ठेकेदार के ठिकानों पर जीएसटी का छापा, दो गाड़ियों में पहुंची टीम

भानुप्रतापपुर। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में माइंस ठेकेदार अरविंद साहू के घर और दफ्तर पर जीएसटी टीम ने शुक्रवार देर रात दबीश दी। दिल्ली और रायपुर से अधिकारियों की संयुक्त टीम दो गाड़ियों में पहुंची। ठेकेदार के ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी में वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जांच की गई।

यह कार्रवाई लगभग रात 11 बजे से 1 बजे तक यानी 2 घंटे चली। जानकारी के मुताबिक, माइंस ठेकेदार अरविंद साहू के बाजारपार स्थित निवास और दल्लीरोड स्थित कार्यालय में एक साथ GST की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ठेकेदार अरविन्द साहू नीको



जायसवाल ग्रुप की खदानों में ठेका लेता है। जांच के बाद कार्यालय से प्रिंटर सहित कुछ महत्वपूर्ण सामान अपने साथ ले जाने की खबर है। पूरी कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि स्थानीय पुलिस को भी इसकी जानकारी नहीं थी।

हालांकि टीम द्वारा कौन-कौन से दस्तावेज या उपकरण जब्त किए गए, इसकी आधिकारिक जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।

बैगा परिवार की सात बेटियों का संघर्ष

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। जिले के वनांचल के सुदूर गांव निजामडीह से मार्मिक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को जो कोई भी देख रहा है उसका दिल पसीज रहा है। यहां रहने वाले एक गरीब बैगा आदिवासी परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है।इस परिवार ने पिछले कई महीनों से संघर्ष और दर्द का अंत हुआ तो तकलीफों के बादल मंडराने लगे। अब ये परिवार किसी तरह अपना गुजर बसर करके ज़िंदगी जीने में जुटा है। निजामडीह गांव में अमर सिंह अपनी पत्नी और सात बेटियों के साथ रहता है।

लड़की की फोटो दिखाकर युवक से ऐंठे पैसे

धमतरी। धमतरी से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के दौर में जहां लोग ऑनलाइन जीवनसाथी तलाश रहे हैं वहीं शातिर ठग इसी भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे। धमतरी में एक युवक को यूनिक रिश्ते दिलाने के नाम पर हजारों की चपत लगा दी गई। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के दानीटोला वार्ड का है। यहां रहने वाले रवि कुमार बघेल को क्या पता था कि एक अनजान फोन कॉल उनकी जेब पर भारी पड़ जाएगा। दरअसल रवि के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने खुद को यूनिक रिश्ते नामक प्लेटफॉर्म से जुड़ा बताया। बातचीत के दौरान युवक को एक लड़की की तस्वीर भेजी गई। फोटो देखते ही युवक शादी के लिए तैयार हो गया, बस यहीं से ठगी का खेल शुरू हुआ। ठगों ने रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर युवक से ऑनलाइन UPI के जरिए पैसे मांगना शुरू किया। महज एक हफ्ते के भीतर युवक से 14,000 रुपए ऐंठ लिए गए।

ब्रेकअप के तनाव में आरोपी ने युवती पर किया चाकू से हमला

कोरबा। कोरबा के पंचवटी के पास ड्यूटी जा रही युवती पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले मुख्य आरोपी और उसके नाबालिग सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया कि वह गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद तनाव में था और रास्ते में मोबाइल पर बात करती युवती को देखकर उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, घटना 27 मार्च 2026 की सुबह करीब पौने 11 बजे की है। सीएसईबी चौकी अंतर्गत पंप हाउस निवासी युवती रोज की तरह पैदल ड्यूटी करने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार दो लोगों ने पीछे से चाकू से हमला कर दिया। युवती को गंभीर रूप से घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। पुलिस ने जांच के दौरान आस-पास के क्षेत्रों के 100 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की। सीपीटीबी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर एक महीने की मशक़त के बाद पुरानी बस्ती धनवार पारा निवासी शक्ति कुमार साहसी 19 वर्ष और उसके नाबालिग साथी का पता चला।

नकली सोना देकर लाखों की ठगने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले के गौरेला थाना क्षेत्र में नकली सोना देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब छह माह से फरार चल रहे आरोपी तेरसाराम प्रजापति (32 वर्ष) निवासी बोकरामुड़ा चौकी कोडगार थाना पेंड्रा, को मुखबिर की सूचना के आधार पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध में अपनी सलिलता स्वीकार कर ली, जिसके बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार, मुंगेली जिले के तिलकपुर निवासी उमेश साहू ने गौरेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी नरेन्द्र साहू, सरोज साहू एवं उनके साथियों ने उसे सोने के बिस्किट मिलाने का झांसा दिया। आरोपियों ने पहले असली सोने का नमूना दिखाकर विश्वास में लिया और 1 किलोग्राम सोना 10 लाख रुपये में देने का सौदा तय किया। 5 दिसंबर 2025 को पीड़ित से नगद राशि लेने के बाद आरोपी नकली सोने के बिस्किट देकर फरार हो गए। बाद में जांच कराने पर सोना नकली निकला।

गौ सेवकों का आंदोलन कलेक्ट्रेट गेट पर मवेशी बांधकर प्रदर्शन

मुंगेली। गौसेवा से जुड़े लोगों का आंदोलन शुक्रवार को उस मोड़ पर पहुंच गया, जहां मामला केवल मांगों तक सीमित न रहकर प्रशासनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की चुनौती बन गया। कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य गेट पर दो दर्जन मवेशी बांधकर शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे सड़क पर चक्काजाम और फिर हाईवे बाधित करने तक पहुंच गया, जिससे पूरा दिन जिला प्रशासन और पुलिस अमले के लिए तनावपूर्ण रहा। पुलिस अफसरों के मुताबिक प्रदर्शनकारी कथित गौसेवक सुबह 9 बजे से ही कलेक्ट्रेट पहुंचने लगे और मुख्य गेट के सामने मवेशियों को बांधकर प्रतीकात्मक विरोध शुरू किया। इसी दौरान घायल और बीमार पशुओं को भी परिसर में लाया गया, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति बन गई। प्रदर्शन का यह तरीका प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए अपनाया गया, लेकिन इससे स्थिति और संवेदनशील हो गई। प्रदर्शनकारी गौसेवकों का दावा है कि लगभग तीन माह पहले उन्होंने भूख हड़ताल की थी।

रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था: काउंटर में नहीं रहते कर्मचारी



खड़े करता है। स्थानीय यात्रियों का कहना है कि यह लापरवाही रोजमर्रा की समस्या बन चुकी है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर रेलवे के आधिकारिक हैंडल्स को टैग कर शिकायत की गई, जिसके बाद रेलवे की ओर से जवाब सामने आया है। रेलवे सेवा (RailwaySeva) ने



अपने जवाब में असुविधा के लिए खेद जताते हुए शिकायत दर्ज कराने के लिए रेल मदद पोर्टल (railmadad.indianrailways.gov.in) पर रजिस्ट्रेशन करने या हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करने की सलाह दी है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराने का बात

भी कही गई है। वहीं डीआरएम संबलपुर (DRMSambalpur) ने संबंधित विभाग को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। एक अन्य जवाब में कहा गया है कि मामले को देखा जा रहा है।

रेलवे की ओर से जवाब आने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई त्वरित सुधार नजर नहीं आया है। यात्रियों का कहना है कि केवल ऑनलाइन जवाब देने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि स्टेशन पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना जरूरी है। रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभाग में जहां समय और अनुशासन सबसे अहम होता है, वहां इस तरह की लापरवाही चिंता का विषय है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि राहुल शर्मा सहित जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए टिकट काउंटर की व्यवस्था को तत्काल सुधारा जाए, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।

संक्षिप्त समाचार

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्यपाल की संवेदनशील पहल



बेहतर स्वास्थ्य और उपचार को लेकर राज्यपाल श्री रमेन डेका द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है। उन्होंने एम्स के दंत रोग चिकित्सा विभाग को अपने स्वेच्छानुदान से 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी, जिसके माध्यम से इन बच्चों के दंत रोगों का उपचार किया जा रहा है। शनिवार को राज्यपाल ने एम्स पहुंचकर दंत रोग चिकित्सा विभाग का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपचार के लिए आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। बच्चों और उनके परिजनों से बातचीत करते हुए उन्होंने उपचार की प्रक्रिया और सुविधाओं के बारे में भी जाना। राज्यपाल ने चिकित्सकों और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सहज स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। एम्स के दंत विभाग में चल रही इस पहल से कई बच्चों को दंत रोगों से राहत मिल रही है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

रायपुर में 10 और 13 मई को आईपीएल का महामुकाबला, आज से टिकट बुकिंग शुरू

रायपुर। राजधानी रायपुर में 10 और 13 मई को आईपीएल मैच होने जा रहा है। इसकी टिकट को बुकिंग आज यानि 3 मई से शुरू रहे रही है। मैच के टिकट केवल आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट shop.royalchallengrs.com/ticket और ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। किसी अन्य वेबसाइट/ऐप से नकली टिकट न खरीदें। बता दें कि 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) बनाम मुंबई इंडियंस और 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होंगे। अब तक अपडेट के मुताबिक आरसीबी की टीम 8 मई को रायपुर पहुंचेगी और यहां 6 दिन तक रहेगी। टीम मैदान पर प्रैक्टिस भी करेगी। मुंबई इंडियंस की टीम भी 8 मई के बाद राजधानी पहुंचने की संभावना है। टिकट आरसीबी की आधिकारिक वेबसाइट से ही ऑनलाइन बुक किए जाएंगे। सबसे सस्ती टिकट 2000 रुपए की होगी। इसके अलावा 2500 रुपए, 3500 रुपए, 5000 रुपए और 8000 रुपए तक की कैटेगरी में होगी। इसके अलावा प्लैटिनम सीटों के सामने लगे कांच के पैनल हटा दिए गए हैं। अब दर्शक खिलाड़ियों को बिना किसी रुकावट के और करीब से देख सकेंगे।

जनगणना कार्य में लापरवाही पर सहायक शिक्षक सत्यजीत निराला निलंबित

रायपुर। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण भवन क्रमांकन एवं मकान सूचीकरण के अंतर्गत प्रगतकों और पर्यवेक्षकों के लिए 15 से 17 अप्रैल 2026 तक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला में तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी (ग्रामीण) दुलदुला के प्रतिवेदन के अनुसार, जशपुर जिले के प्राथमिक शाला सरहापानी, ग्राम पतराटोली के सहायक शिक्षक श्री सत्यजीत निराला बिना पूर्व सूचना या अनुमति के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे। इस पर उन्हें 19 अप्रैल 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।इसके बाद जिला स्तर से भी 21 अप्रैल 2026 को पुनः नोटिस जारी किया गया, परंतु संबंधित द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया। प्रकरण में स्पष्ट हुआ कि श्री निराला ने जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना की। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 का उल्लंघन माना गया है। इसी आधार पर श्री सत्यजीत निराला को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निर्लंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, दुलदुला कार्यालय निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

रायपुर के प्रयास विद्यालयों में 9वीं प्रवेश परीक्षा 10 मई को

रायपुर। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026–27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्रयन परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र 1 मई 2026 से 10 मई 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी अंतिम तिथि 10 मई को प्रातः 9:30 बजे तक निर्धारित की गई है। प्राक्रयन परीक्षा 10 मई 2026 को आयोजित होगी, परीक्षा प्रोग्राम 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक संचालित होगी। विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र https://eklayva.cg.nic.in वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राजधानी/छत्तीसगढ़

वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें : साय

■मुख्यमंत्री ने सुरक्षा ऑडिट एवं सतत मॉनिटरिंग के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई करूज हादसे की दुखद घटना के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संचालित सभी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करते हुए सुरक्षा मानकों का सुदृढ़ता से पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन सुरक्षा के विषय में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य होगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने धमतरी और कोरबा सहित अन्य सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया कि जिन स्थलों पर वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां सुरक्षा मानकों का तत्काल परीक्षण (सुरक्षा ऑडिट) सुनिश्चित किया जाए तथा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अक्षरशः पालन कराया जाए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने निर्देश



दिए कि सभी संबंधित वाटर स्पोर्ट्स स्थलों पर उपयोग में लाए जा रहे उपकरणों का नियमित तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित किया जाए, प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन की तैनाती की जाए, तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु समुचित आपातकालीन प्रबंधन तंत्र सक्रिय रखा जाए। इसके साथ ही रेस्क्यू उपकरणों, लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता एवं कार्यशील स्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने कलेक्टरों को यह भी निर्देशित किया कि वे इन व्यवस्थाओं की सतत

निगरानी करें तथा किसी भी स्तर पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित अधिकारियों/संचालकों की जवाबदेही निर्धारित करते हुए आवश्यकतानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन नागरिकों एवं

पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पूर्णतः सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं मानक अनुरूप संचालित हों, जिससे संभावित जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए कि इन सभी व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए और समय-समय पर इसकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि सतर्कता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करते हुए ही हम जन-जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।

सावित्री बाई फुले शिक्षक महासंघ का राज्य इकाई गठित, श्वेता बनी संभागाध्यक्ष

रायपुर। सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला शिक्षक फेडरेशन (पंजी) नई दिल्ली की राष्ट्रीय महिला शिक्षक महासंघ द्वारा रायपुर के वृंदावन हॉल में पिछले दिनों एक गरियामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां कुछ शिक्षकों का सम्मान किया गया वहीं राज्य इकाई का भी गठन किया गया जिसकी श्वेता ठाकुर को संभाग अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इस दौरान उन्होंने शपथ ग्रहण कर अपना पदभार ग्रहण किया।

इस अवसर पर महासंघ की संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लता एस मुद्गूर, मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति संचार एवं संपर्क जिला पंचायत रायपुर स्वाति वर्मा,

राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सारिका एस गंगा कल्पना, बुत रेड्डी, अनुमूया देवी, पी भाय्यमा, सिधोज कविता, राजश्री प्रभावती, शांताबाई बिरादर, अतिथि वक्ता के रूप में नर्मदा प्रसाद मिश्र, डॉक्टर मनीष वत्स, विष्णु दत्त बघेल एवं डीएसपी रूचि वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थी।

कार्यक्रम का संयोजन लोकेश कुमार द्वारा किया गया। इस संगठन की

संभाग अध्यक्ष श्वेता ठाकुर है, जिन्हें उनके शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य व समाज सेवा एवं साहित्य के क्षेत्र में सुजनात्मक कार्य हेतु सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला शिक्षक फेडरेशन पंजी नई दिल्ली के द्वारा सम्मानित किया गया। इसके अलावा जशपुर के छह शिक्षकों का सम्मान किया गया जिसमें चार

शिक्षकों को नवाचारी शिक्षक के रूप में एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर महिला शिक्षकों की शक्ति, एकता एवं उपलब्धियां को प्रदर्शित करने का एक भव्य मंच है जिसमें पहली बार छत्तीसगढ़ के शिक्षक - शिक्षकों को भी शामिल होने का अवसर मिला और उनकी प्रतिभा को एक उपयुक्त मंच भी।

नीट (यूजी) 2026 परीक्षा हेतु सभी तैयारियां पूर्ण, आज होगी परीक्षा

रायपुर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए.) द्वारा आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा का आयोजन 03 मई 2026, रविवार को देशभर के साथ रायपुर जिले में भी किया जाएगा। परीक्षा के सुचारू एवं सफल संचालन हेतु नीट जिला समन्वयक एवं जिला प्रशासन

द्वारा आवश्यक सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बैठक में परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। परीक्षा के सफल संचालन हेतु सभी केंद्राध्यक्षों एवं पर्यवेक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें।

जिला नोडल अधिकारी (एन.टी.ए.) ने जानकारी दी कि रायपुर जिले में कुल 26 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परीक्षार्थियों को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं

दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा केंद्रों में नकल प्रकरणों की रोकथाम हेतु तकनीकी संसाधन भी स्थापित किए गए हैं, जिससे परीक्षा निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से हो सके।

जिला प्रशासन द्वारा परीक्षार्थियों से अपील की गई है कि वे समय से पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचें तथा प्रवेश पत्र में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री नवीन ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राहुल देव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती नंदनी ठाकुर, जिला नोडल अधिकारी (एन.टी.ए.) श्रीमती लक्ष्मी सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी श्री हिमांशु भारती, रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल, एन.आई.सी. के श्री पी.सी. वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भारतमाला परियोजना घोटाला : संभाग स्तर पर दो नई टीम गठित

■ हर खसरे की होगी अब जांच

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जांच कर रही है, लेकिन अब इस मामले में प्रशासनिक दखल के तहत रायपुर संभाग आयुक्त महादेव कांकरे ने भी भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में जांच के लिए दो अलग-अलग टीमों का गठन किया है। जिसमें एक टीम धमतरी जिले में और दूसरी टीम रायपुर जिले में जांच करेगी। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रशासन ने इस बार सभी खसरा नंबरों की बारीकी से जांच करने का निर्णय लिया है। ताकि मुआवजा वितरण में किसी तरह की अनियमितता या फर्जीवाड़ा की पूरी तरह से पड़ताली को



जा सके।

रायपुर के संभाग आयुक्त महादेव कांकरे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो अलग-अलग टीम का गठन किया है। जिसमें एक टीम धमतरी जिले में जांच करेगी और दूसरी टीम रायपुर जिले में जांच करेगी। इन गठित टीमों को संभाग आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी एक एक खसरा की बारीकी से जांच करें। ताकि भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला की वास्तविक स्थिति पता चल सके।

संभाग आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर जिले के खसरा नंबरों की जांच डिप्टी कलेक्टर ज्योति सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है।

वही धमतरी जिले के लिए संबंधित खसरा नंबर की जांच अपर कलेक्टर पवन कुमार की टीम को दी गई है। दोनों टीमों को एक महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। जांच में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं।

निर्माण गुणवत्ता में जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने संबंधी प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हिलाई या लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सीसी रोड का तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समग्र जांच की जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का त्वरित रूप से

पुनर्निर्माण कर आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में संचालित अन्य निर्माण कार्यों की भी विशेष समीक्षा की जाए, ताकि कहीं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की मूल जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विकास कार्यों की विश्वसनीयता बढ़ा टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है – जनहित के प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।

समग्र ब्राह्मण परिषद् द्वारा महामाया मंदिर में 71 बटुकों का उपनयन संस्कार आज

रायपुर। उत्कृष्ट ब्राह्मण सामाजिक संगठन समग्र ब्राह्मण परिषद् छत्तीसगढ़ द्वारा रविवार 3 मई को पुरानी बस्ती स्थित प्राचीन श्री महामाया मंदिर प्रांगण स्थित सत्संग भवन में धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश स्तरीय सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71 ब्राह्मण बटुकों का विधिवत संस्कार संपन्न होगा. यह कार्यक्रम विशेष रूप से वैदिक परंपराओं के संरक्षण और नई पीढ़ी को संस्कारों से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है.

संगठन के मुख्य सलाहकार एवं कार्यक्रम संयोजक डा.भावेश शुक्ला पराशर एवं महामाया मंदिर व्यवस्थापक पं विजय कुमार झा ने आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि संस्कार से पहले पारंपरिक विधियों जैसे तेलमाटी, मंडपाच्छादन, मातृका पूजन और हरिद्रालेपन आदि अनुष्ठान संपन्न किए जाएंगे। इसके बाद बटुकों का



मुंडन संस्कार और फिर यज्ञोपवीत धारण कराया जाएगा. आचार्यों द्वारा उन्हें गायत्री मंत्र दीक्षा एवं जीवन के धार्मिक-सांस्कृतिक कर्तव्यों की शिक्षा दी जाएगी. अंत में बटुकों द्वारा भिक्षा-वृत्ति की परंपरा का प्रतीकात्मक निर्वहन भी कराया जायेगा.

संगठन के प्रदेश सचिव पं.सजल तिवारी ने बताया कि इस प्रकार के सामूहिक उपनयन कार्यक्रम पहले भी परिषद् द्वारा आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बटुकों ने भाग लेकर वैदिक परंपराओं को आगे बढ़ाया है. इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के ब्राह्मण बटुक इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री झा ने बताया है कि दोपहर यज्ञोपवीत संस्कार में लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम पश्चात संध्या 6 बजे शोभायात्रा बाजे-गाजे, अतिश बाजी के साथ महामाया मंदिर से ठेठ वार भवन, अग्रसेन भवन, जैतू साव मठ, एवं दक्षिण मुछ्ही हनुमान मंदिर बावली से होते हुए वापस महामाया मंदिर रामगढ़ पहुंचेगी।

ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का ऐलान छत्तीसगढ़ से गुरुचरण सिंह होरा को मिली संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी

नई दिल्ली/रायपुर। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (एआईटीए) की चुनाव प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई और सभी उम्मीदवार अपने-अपने पदों पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सुरिंदर गोयल ने चुनावों के परिणाम घोषित किया है।

आधिकारिक घोषणा के अनुसार, चिंनन पांरिख को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया गया है। महासचिव के पद पर सुंदर अय्यर का चयन किया गया है, साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली है।

छत्तीसगढ़ से गुरुचरण सिंह होरा को ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में संयुक्त सचिव (पश्चिम) चुना जाना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय माना जा रहा है। उनके इस महत्वपूर्ण पद पर चयन को खेल जगत में एक बड़ी उपलब्धि के रूप



में देखा जा रहा है। गुरुचरण सिंह होरा लंबे समय से खेल और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता से संगठन को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी नियुक्ति से न केवल छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा है, बल्कि प्रदेश के खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों को भी नई दिशा मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

उपाध्यक्ष पद के लिए 8 सदस्यों का चयन किया गया है, जिनमें अनिल धूपर, असित त्रिपाठी, हिरोनम्य चटर्जी, प्रेमकुमार करी, राजन कश्यप, रक्तिम

सैकिया, रोहित राजपाल और सुमन कपूर शामिल हैं। महासचिव के पद पर सुंदर अय्यर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं संयुक्त सचिव (पश्चिम) के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा की जिम्मेदारी मिली है, कैप्टन मुर्ति गुप्ता (उत्तर), डॉ. सुजीत रॉय (पूर्व) और सुनील याजमान (दक्षिण) का चयन हुआ है। कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश अरोड़ा निर्वाचित हुए हैं। होरा को संयुक्त सचिव निर्वाचित होने पर छ्ठा टेनिस संघ के पदाधिकारियों अवतार सिंग जुनेजा, जी एस बांबरा, डॉ सूरज अग्रवाल, डॉ अजय पाठक, डॉ अतुल शुक्ला, सुशील बालानी, सुनील सुराना, प्रदीप माथानी, चरणजीत ओबेरॉय रूपेंद्र सिंह चौहान हेनरी, रोहीन सेंटियागो, नेल्सन जतिन कुमार, राजेश मिश्रा सहित समस्त खिलाड़ियों ने बधाई दी।

पीएम राहत योजना में प्रदेश को मिली बड़ी सफलता

रायपुर। केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना के तहत जिले में एक अहम उपलब्धि दर्ज की गई है। इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है। यह सुविधा आयुष्मान पंजीकृत और सरकारी अस्पतालों में लागू है।

जिले में मोतीबाग चौक निवासी 83 वर्षीय श्री स्माइल खान को इस योजना का लाभ दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश चौधरी ने बताया कि यह राज्य का पहला मामला है, जिसमें लाभार्थी को योजना के तहत स्वीकृति मिली है। डॉ. चौधरी ने बताया कि कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के

समर्पदर्शन में योजना के लाभ हेतु समस्त प्रक्रिया तेज गति से पूरी की गई। पुलिस सत्यापन में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय और पुलिस विभाग का सहयोग रहा। जिला नोडल अधिकारी डॉ. सार्थक नंदा ने पूरी प्रक्रिया की निगरानी की। डॉ.के.एस. अस्पताल में अधीक्षक डॉ. शिप्रा शर्मा और उप अधीक्षक डॉ. हेमंत शर्मा के नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने सभी जरूरी औपचारिकताएं समय पर पूरी कीं, जिससे लाभार्थी को बिना देरी भुगतान स्वीकृत हो सका। जिले में वर्तमान में 10 मामले इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं।

महिला आरक्षण : राजनीति का शिकार या खानापूूर्ति

ऋतुपर्ण दत्ते

क्या महिला आरक्षण बिल यानी अब नारी वंदन अधिनियम–2023 राजनीति का शिकार हो गया है या फिर सभी की अनिच्छा के चलते महज औपचारिक हो– हल्के के बीच खानापूूर्ति कर ली गई। यदि कहें कि इस पर किसी भी दल ने गंभीरता नहीं बरती तो गलत नहीं होगा। भले पक्ष–विपक्ष दोनों में ही इस पर तकरार करें लेकिन नीयत किसी की समझ नहीं आती। हालांकि इतना समझ आता है कि अभी इसके कार्यान्वयन में देरी का कारण मुख्यतः राजनीतिक लाभ और परिसीमन है। सतारूढ़ दल एक तौर से दो शिकार करना चाहता था तो विपक्ष इसके पीछे छिपी नीयत को उजागर करना। हां, पक्ष–विपक्ष दोनों ही अपनी–अपनी राजनीति जरूर कर रहे हैं, पर शिकार नारी वंदन अधिनियम बिल हुआ। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उससे लगता है कि 33 प्रतिशत का महिला आरक्षण अब जनगणना और परिसीमन की आड़ में 2029 तक टल गया है। वजह जो भी हो, जनता और विशेषकर देश की आधी आबादी को सब समझ आ रहा है क्योंकि बीते 30 वर्षों में 7 बार ऐसा हो चुका है। इस पर अब तक हुई राजनीति को भी समझना होगा। महिला आरक्षण पर संसद में पहली बार 1990 के दशक में चिंता की गई। 1996 में पहली बार एच.डी. देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार में नाकाम कोशिशें हुईं और 12 सितम्बर, 1996 को 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ। तब भी भारी हंगामे के बीच गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया लेकिन लोकसभा भंग होने से विधेयक लैप्स हो गया। कोशिश 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान फिर हुई और लगा कि इस बार सफलता तय है। 20 सितम्बर, 2023 को नए संसद भवन के पहले सत्र में मोदी सरकार ने इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से पेश किया। दोनों सदनों में पारित होकर कानून भी बना। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी गई कि यह परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू होगा इसलिए लटक गया। सातवीं बार 17 अप्रैल, 2026 को फिर इस पर असफलता हाथ लगी। लोकसभा में इस कानून को तत्काल प्रभावी बनाने और परिसीमन से जुड़े संशोधनों पर मतदान हुआ। जरूरी बहुमत से सरकार 54 वोट पीछे रह गई और बिल का वही हश्र हुआ जो छः बार हो चुका था। इस सच्चाई को भी समझना होगा कि अभी लोकसभा में महिलाओं की संख्या करीब 14 प्रतिशत और राज्यसभा में लगभग 17 प्रतिशत है, जबकि राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी औसत महज 10 प्रतिशत के आसपास ही है। आधिकारिक तौर पर भारत को संसद में वर्तमान में महिलाओं के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से इसे विडंबना कहें या साजिश या फिर कुछ और लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हां, यह पहला मौका भी नहीं था और जिस तरह की राजनीति समझ आ रही है शायद आखिरी भी न हो, जब यह बिल लोकतंत्र के मंदिर में सम्मान पूर्वक पारित हो सके। दरअसल, ‘महिला आरक्षण विधेयक’ एक ऐसा अध्याय बन चुका है, जो बार–बार संसद की दहलीज तक तो पहुंचता है लेकिन किसी सकारात्मक निर्णय पर पहुंचने के पहले ही राजनीति का शिकार हो जाता है। क्या यह देश की आधी आबादी के प्रति दिखावा है या संशा कुछ और ही है। बीते 7 बार का घटनाक्रम देखें तो इतना तो समझ आता है कि सरकार में भले ही कोई रहे, महिलाओं के हक को लेकर बात करने वालों के हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और समझ आते हैं। कितना अच्छा होता कि बिना किसी विवाद के पूरी पारदर्शिता से नारी वंदन की सोच कानून बन पाती और आधी आबादी की खातिर कम से कम 33 प्रतिशत सीटें सुरक्षित हो जातीं।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

(घ) सौमाम्नो (सोमपुत्रः) बुधः ।

(ताण्ड्य 24।17।6)

अर्थात्– (क) सोम पहिला राजा हुवा, जिसने ब्राह्मण [= बृहस्पति] की धर्मपत्नी (घरमें रखकर) निलिन्जनापूर्वक पुनः वापिस दी।

(ख) जिस स्त्री को विवृद्धकेशों वाली तारका ऐसा कहा जाता था। (ग) उस सोम द्वारा हठात् छीनी गई अपनी स्त्री को बृहस्पति ने प्राप्त किया। (घ) सोम = चन्द्रमा का पुत्र बुध हुआ।

पौराणिक–स्वरूप

उक्त आख्यान का पौराणिक–स्वरूप तथा आधिभौतिक अर्थ इसी ग्रन्थ में पृष्ठ 266 से पृष्ठ 267 तक लिखा जा चुका है, पाठकों को वहाँ देखना चाहिये, यहाँ पिप्रेषेण करने की आवश्यकता नहीं ।

उपर्युक्त मन्त्र ऋवेद (8।6।7।–) में इसी प्रकार आए हैं वहाँ सायणाचार्य ने अपने भाष्य में इनकी

इतिहासपरक ही व्याख्या की है इन मन्त्रों में कितनी स्पष्टता के साथ यह श्राख्यान वर्णित है– यह कहने की आवश्यकता नहीं।

आध्यात्मिक अर्थ

स्वर्गाय श्री पं0 कालूराम जी शास्त्रा ने उक्त आख्यान का निम्न–लिखित आध्यात्मिक भाव प्रकट किया है–

यहां पर गुरु को बृहस्पति के नाम से याद किया गया है, और आल्हादयुक्त शिष्य को चन्द्रमा कहा है। गुरु विद्या में रमण करता है, इस विद्या को गुरुपत्नी लिखा है, वह साधारण नहीं है, वह तारा है, तार–यति संसार–सागरात् या सा तारा– विद्या संसार सागर से जो पार उतारती है उस विद्या का नाम तारा है। शिष्य गुरु को विद्या को ग्रहण कर लेता है, उस विद्या से शिष्य के अन्तःकरण में ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान को यहाँ पर बुध लिखा है।

क्रमशः ...



ज्ञान/मीमांसा

नीरज कुमार दुबे

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर प्रस्तावित विकास परियोजना को लेकर देश में तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना को देश की प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध और घोटाला बताया है। उन्होंने अपने तौरे के बाद कहा कि यहां के घने जंगल, जो सदियों में विकसित हुए हैं, अब बड़े पैमाने पर काटे जाने के खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 160 वर्ग किलोमीटर वर्षावन क्षेत्र को समाप्त किया जाएगा और लाखों पेड़ों की कटाई होगी, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है। राहुल गांधी ने इसे विकास के नाम पर विनाश बताया और कहा कि वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। उनका आरोप है कि स्थानीय समुदायों की सहमति के बिना उनकी जमीन और संसाधनों को छीना जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की ओर से पहले ही इस परियोजना को लेकर चिंता जताई गई थी, जिसमें इसे शॉपेन जनजाति और द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बताया गया। सोनिया गांधी ने इस मुद्दे को उठाते हुए समाचार–पत्रों में एक विस्तृत लेख लिखा था।

दूसरी ओर, इस परियोजना को देश की सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीति आयोग द्वारा तैयार और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत इस योजना की लागत लगभग 8।000 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसमें चार प्रमुख घटक शामिल हैं, जिनमें एक विशाल ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऊर्जा संयंत्र और सैन्य ढांचे का विस्तार शामिल है। हम आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है। यह मलक्का जलडमरूमध्य के प्रवेश द्वार के पास स्थित है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। चीन का लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात और उसका बड़ा व्यापार इसी मार्ग से गुजरता है। ऐसे में इस क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति उसे सामरिक बढ़त दिला सकती है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि गैलैथिया खाड़ी में बनने वाला बंदरगाह भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार में नई पहचान दिला सकता है। हम आपको बता दें कि वर्तमान में भारत का लगभग 25 प्रतिशत माल विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से



स्थानांतरित होता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। इस परियोजना के पूरा होने पर भारत इस निर्भरता को समाप्त कर सकता है और अपनी समुद्री शक्ति को मजबूत कर सकता है।

चीन की रणनीति को देखते हुए यह परियोजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पिछले दो दशकों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में कई बंदरगाह विकसित किए हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इनमें पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बन्टोटा और म्यांमार का क्याउकपयू शामिल हैं। इनका उद्देश्य समुद्री मार्गों पर प्रभाव बढ़ाना और भारत को घेरना है।

इसके जवाब में भारत ने भी अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर समुद्री रणनीति विकसित की है, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। इसमें ओमान, इंडोनेशिया और सेशेल्स जैसे देशों में बंदरगाहों तक पहुंच और सैन्य सहयोग शामिल है। ग्रेट निकोबार इस रणनीति का केंद्र बिंदु माना जा रहा है।

इसके अलावा, हाल के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम भी इस परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हैं। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के उपयोग से वैश्विक तेल आपूर्ति पर प्रभाव डालने की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किसी भी देश के लिए कितना शक्तिशाली साधन हो सकता है। इस स्थिति में यदि भारत मलक्का जलडमरूमध्य के पास अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो यह उसे वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बना सकता है।

मोदी सरकार का कहना है कि परियोजना को पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा मानकों के तहत स्वीकृति दी गई है। शॉपेन जनजाति की सुरक्षा के लिए विशेष नीतियां, नितरानी तंत्र और अन्य उपाय लागू किए गए हैं। सरकार के अनुसार परियोजना द्वीप के कुल क्षेत्रफल के

सीमित हिस्से पर ही आधारित है और विकास तथा संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया है। हम आपको यह भी बता दें कि इस परियोजना का विरोध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। कुछ विदेशी संगठनों ने इसे जनजातीय अस्तित्व के लिए खतरा बताया है। लेकिन इस परियोजना के रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह साफ नजर आ रहा है कि चीन के समर्थक कभी नहीं चाहेंगे कि भारत की यह परियोजना साकार रूप ले सके।

उधर, रक्षा विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है और इस पर आगे बढ़ने का समय आ गया है। पूर्व वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया ने विभिन्न साक्षात्कारों और समाचारपत्रों में अपने आलेखों के जरिये इस परियोजना की महत्ता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि विपक्ष के नेता ने हाल में इस द्वीप का दौरा किया और सोशल मीडिया के माध्यम से परियोजना को इकोलॉजी और पर्यावरण के विनाश का कारण बताते हुए एक बड़ा घोटाला और १%राष्ट्रीय धरोहर के खिलाफ अपराध% करार दिया। उन्होंने लिखा है कि पर्यावरण की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य की रणनीतिक दिशा की बात हो, तो तत्क्षीर का केवल एक हिस्सा देखना उचित नहीं लगता। यह परियोजना देश के भविष्य की एक सख्त सामरिक और आर्थिक आवश्यकता है।

आर.के.एस. भदौरिया लिखते हैं कि भारत लंबे समय तक अपनी सुरक्षा सोच में भूमि–सीमाओं पर अधिक केंद्रित रहा। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक शक्ति का केंद्र है। ग्रेट निकोबार का भूगोल अपने आप में भारत के लिए एक प्राकृतिक वरदान है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का लगभग 30% कंटेनर व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। उन्होंने लिखा है कि मैंने अपने कैरियर में कई बार महसूस किया कि जब आपकी नितरानी की क्षमता सीमित होती है, तो आपकी प्रतिक्रिया भी सीमित हो जाती है।

देवर्षि नारद जयंती



साधक माना गया है। उन्हें ब्रह्माण्ड का पहला ऐसा संदेशवाहक अर्थात् पत्रकार माना जाता है, जो एक लोक से दूसरे लोक की परिक्रमा करते हुए सूचनाओं का आदान–प्रदान किया करते थे।

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि 2 मई 2026 को रात 12 बजकर 51 मिनट से शुरू होगी और 3 मई को रात 3 बजकर 2 मिनट तक रहेगी।

उदया तिथि के आधार पर 3 मई को नारद जयंती मनाया शुभ और शास्त्रसम्मत माना गया है। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन

भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात् देवर्षि नारद की पूजा की जाती है। अपनी वीणा की मधुर तान से भगवान विष्णु का गुणगान करने और अपने श्रीमूख से सदैव नारायण–नारायण का जप करते हुए विचरण करने वाले नारद को महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि तथा महाज्ञानी शुक्रदेव का गुरु माना जाता है। कुछ शास्त्रों में नारद मुनि को त्रिकालदर्शी और विष्णु का अवतार भी माना गया है। श्रीमद्भागवदपुराण के अनुसार सृष्टि में भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया है। कुछ स्थानों पर उनका वर्णन बृहस्पति के शिष्य के रूप में भी मिलता है।

धार्मिक पुराणों के अनुसार अनेक कलाओं तथा विद्याओं में निपुण देवर्षि नारद को संगीत की शिक्षा ब्रह्माजी ने स्वयं दी थी और भगवान विष्णु ने उन्हें माया के

विविध रूप समझाए थे। मान्यता है कि देवर्षि नारद ने ही भक्त प्रह्लाद, भक्त अम्बरीष, भक्त ध्रुव इत्यादि भगवान विष्णु के कई परम भक्तों को उपदेश देकर उन्हें भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया था। उन्होंने ही भृगु कन्या लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराया। देवराज इन्द्र को समझा– बुझाकर देव नर्तकी उर्वशी का पुरस्वा के साथ परिणय सूत्र कराया। इसके अलावा वे कई अत्याचारी महाराक्षसों द्वारा जनता के उत्पीड़न का वृत्तांत भगवान तक पहुंचाकर उनके विनाश का माध्यम भी बने। महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण है कि समस्त युगों, कालों, विधाओं और वर्गों में सम्मान के पात्र रहे नारद जी को सभी लोकों के समाचारों की जानकारी रखने वाले कवि, मेधावी नीतिज्ञ तथा एक प्रभावशाली वक्ता के रूप में स्मरण किया जाता है।

आज का इतिहास

- 1815 तोलेटीनो की लड़ाई में ऑस्ट्रिया ने नेपल्स राजा जोआचिम को हराया।
- 1837 यूनान में एर्थेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।
- 1845 चीन के कैंटन में थियेटर में आग लगने से 1600 लोगों की मौत हुई।
- 1855 अमेरिकी साहसी विलियम वॉकर और सैन फ्रांसिस्को से भाड़े का एक समूह निकारागुआ को जीतने के लिए।
- 1887 एक भूकंप के झटके से सोनोरा और मैक्सिको पूरी तरह हिल गया।
- 1913 पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई।
- 1915 सबसे पुराना लगातार चालू रॉयल एयर फोर्स स्टेशन, आरएएफ नॉर्थॉल्ट, नंबर 4 रिजर्व एयरबैल स्ट्रोकडून के लिए घर के रूप में खोला गया।
- 1915 कनाडाई चिकित्सक और लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मैके ने इनफैंटेंस फील्ड्स लिखा, जिसे बाद में प्रथम विश्व युद्ध में सबसे उल्लेखनीय कविताओं में से एक माना गया।
- 1920 11 वीं सोवियत रेड आर्मी पर भरोसा करते हुए पड़ोसी देशों में काम कर रहे बोल्लेविकों ने जॉर्जिया में तख्तापलट की कोशिश की।
- 1921 आयरलैंड द्वीप को दो अलग–अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था: उत्तरी और दक्षिणी आयरलैंड।
- 1926 ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ने घोषणा की कि एक सामान्य हड़ताल 3 मई, 1926 को शुरू होनी थी। यह हड़ताल ब्रिटिश सरकार को मजदूरी में कमी और 8, 00,000 लॉक–आउट कोयला खनिकों के लिए बिगड़ती परिस्थितियों को रोकने के लिए 9 दिन चली थी।
- 1929 ब्लाइ एले की लड़ाई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक रेजर रफ़्ट द्वारा लड़ी गई थी।
- 1942 द्वितीय विश्व युद्ध–जापानी बलों ने सोलोमन द्वीप समूह में तुलागी और आसपास के द्वीपों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिससे वे संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच आपूर्ति और संचार मार्गों को खतरे में डाल सकते हैं।
- 1945 द्वितीय विश्व युद्ध–जर्मन महासागर लाइनर कैप अरकोना, बोर्ड पर हजारों कैदियों से सनातनी शिविरों के साथ लुबेक की खाड़ी में तैरने के लिए छोड़ दिया गया था, आरएएफटी यफून द्वारा हमला किया गया था और डूब गया था।
- 1951 रॉयल फेस्टिवल हॉल, ग्रेट ड्रु को पहले युद्ध के बाद की इमारत, ब्रिटेन के महोत्सव के लिए स्थल के रूप में खोला गया।

यूपी के विकास का एक्सप्रेस वे बनेगा गंगा एक्सप्रेस वे

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश में अवस्थापना विकास के क्रम में निर्मित गंगा एक्सप्रेस वे आम जनमानस के लिए खुल रहा है जिसे प्रदेश के विकास में मील का पथर माना जा रहा है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेस वे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने वाला पहला सीधा हाई स्पीड एक्सप्रेस वे है। इस परियोजना पर 36,230 करोड़ की लागत आई है। यह एक्सप्रेस वे मेरठ के बिजौली गाँव से प्रारंभ होकर बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, उन्नाव, हरदोई, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले के जुड़ापुर दादू गांव तक जाएगा। इस एक्सप्रेस वे के प्रारंभ हो जाने के बाद देश के एक्सप्रेस वे नेटवर्क में यूपी की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत हो जाएगी और परियोजनाओं की कुल लंबाई 1910 किमी हो जाएगी। छह लेन का यह एक्सप्रेस वे पूरी तरह ग्रीनफील्ड व एक्सेस-कंट्रोल्ड है। इसमें 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड, 17 टोल प्लाजा 8 मुख्य पुल और 381 अंडरपास शामिल हैं।

यह भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेस है जिस पर होटल, ढाबा और ईवी चार्जिंग स्टेशन से लेकर अस्पताल तक बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेस वे पर विश्वस्तरीय फूड चैन और

मोटेल तक की सुविधाएं मिलेंगी। 594 किमी लंबे इस एक्सप्रेस वे का 80 प्रतिशत निर्माण अडानी इंटरप्राइजेज ने किया है। अडानी ने प्रयागराज से बदायूं तक 464 किमी लंबा एक्सप्रेस वे बनाया है जबकि शेष 20 प्रतिशत आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बनाया है। एक्सप्रेस वे मतल्टीनेशनल चैन भी उपलब्ध- एक्सप्रेस वे पर लखनऊ के खानपान और चिकनकारी की झलक दिखाई पड़ेगी। इस वे पर एक बड़ा डाइनिंग फूड एरिया विकसित किया गया है। पहली बार किसी एक्सप्रेस वे पर ट्रक लेन बनाया गया है। मोटेल भी तैयार हो गया है जहां विश्राम के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कमरे उपलब्ध हैं। स्टारबक्स जैसे बड़े ब्रांड के साथ गंगा भोग ढाबा भी है। इसमें लोकप्रिय मुरथल ढाबे को लाने का भी प्रयास चल रहा है। यहां पर एक ट्रामा सेन्टर भी तैयार किया गया है। एक्सप्रेस वे पर सुविधा केंद्रों में बच्चों के लिए चिल्ड्रन प्ले एरिया भी बनाया गया है जहां बच्चों के खेलने के लिए झूला पार्क भी बनाया गया है(झड़वरां के लिए भी अलग-अलग विश्राम एरिया बनाया गया है। हर क्षेत्र में वाहनों के लिए सर्विस सेंटर बनाया गया है। यह एक्सप्रेस वे 12 जिलों को जोड़ते हुए प्रयागराज से मेरठ की दूरी मात्र 6 घंटे में समेट देगा। वाहनों की 120 किमी प्रति घंटा गति,



एयर स्ट्रिप्स, हाईटेक टोल और दुर्घटना रोकने वाली अलर्ट स्ट्रिप्स जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस यह एक्सप्रेस वे प्रदेश की कनेक्टिविटी के परिदृश्य को बदलकर रख देगा।

वायुसेना के लिए भी अहम बनेगा एक्सप्रेस वे- यह एक्सप्रेस वे नागरिकों का सफर आसान बनाने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत भी बनने वाला है। एक्सप्रेस वे पर शाहजहांपुर के जलालाबाद में 3.5 किमी की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। आपातकालीन स्थिति व युद्ध होने पर रणनीतिक तौर पर यह हवाई पट्टी लड़ाकू विमानों के उतरने व उड़ान भरने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस हवाई पट्टी का निर्माण सभी प्रकार के लड़ाकू व परिवहन विमानों के हिसाब से किया गया है।

इस पर राफेल सुबोई-0 एमकेआई मिराज 2000 जगुआर और मिग 29 जैसे लड़ाकू और सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस और एएन -32 जैसे वायुसेना के विमान उतरने के साथ-साथ उड़ान भी भर सकेंगे। इस पर रात में भी लड़ाकू विमानों के उतरने और उड़ान भरने की सुविधा होगी। इसके लिए एक्सप्रेस वे पर प्रीसिज़न अप्रोच लाइटिंग सिस्टम व उन्नत नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही हाई इंटेसिटी रनवे लाइटिंग का उपयोग किया गया है। हवाई पट्टी की सुरक्षा के लिए 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जो किसी भी आपातकालीन स्थिति पर नजर रखने के लिए सहायक हैं।

इस एक्सप्रेस वे का संचालन पूरी तरह आरम्भ हो जाने के बाद 12 जिलों के

औद्योगिक विकास को गति मिलेगी जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पलायन कम होगा। प्रदेश सरकार की योजना इसके किनारे 27 औद्योगिक क्लस्टर बनाने की है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और आवंटन चल रहा है। इससे रसद आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण वस्त्र उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। मेरठ के खेल उद्योग, हापुड़ के हथकरघा, बदायूं के जरी जरदोजी और प्रयागराज के कृषि उत्पादों को अब दिल्ली और पूर्वांचल के बाजारी तक पहुंचना आसान होगा।

प्रमुख विशेषताएं- इस एक्सप्रेस वे की पूरी सड़क पर जल संचयन प्रणाली लगाई गई है ताकि वर्षा का जल सीधे जमीन के अंदर जाए और भूजल स्तर पर बना रहे। यह भारत का सबसे लंबा निरंतर नियंत्रित प्रवेश एक्सप्रेस वे है जहां आबारा पशुओं व स्थानीय यातायत के अनियंत्रित प्रवेश को पूरी तरह से रोका गया है। यह परियोजना टिकाऊ इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके निर्माण में भारी मात्रा में कोयले की राख का उपयोग किया गया है जो प्रदूषण कम करने में सहायक है। पहले सभ्यताएं नदियों के किनारे बसती थीं किंतु अब एक्सप्रेस वे के किनारे होती हैं इसे ध्यान में रखते हुए एक्सप्रेस वे किनारे 18 लाख से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। गंगा

एक्सप्रेस वे के निर्माण की गुणवत्ता को एक्सीलेंट रेटिंग मिली है।

विशिष्ट सुरक्षा तकनीक भी- यहां पर विशिष्ट सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया गया है। सड़क के दोनों किनारों पर क्वाइट एलर्ट स्ट्रिप्स लगाई गई है। यदि किसी चालक को झपकी आ जाए और वाहन इन स्ट्रिप्स पर चढ़ जाए तो तेज कंपन और आवाज पैदा होगी जिससे चालक तुरंत सतर्क हो जाएगा और दुर्घटना टल जाएगी। इस सड़क पर चलने के दौरान झटके और कंपन महसूस नहीं होंगे। मॉडर आर्थिकी व पर्यटन को गति मिलेगी- गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण हो जाने के बाद अब मॉडर आधारित आर्थिकी व पर्यटन को भी गति मिलेगी। यह एक्सप्रेस वे यात्रा को ही आसान नहीं करेगा अपितु प्रदेश में आध्यात्मिक व धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेस वे से प्रमुख आध्यात्मिक व धार्मिक स्थल जुड़ रहे हैंडु इनमें गढ़मुकेश्वर, कल्कि धाम, बेल्वा देवी धाम, चंद्रिकादेवी शक्ति पीठ और त्रिवेणी संगम शामिल हैं। एक्सप्रेस वे शुरू हो जाने के बाद श्रद्धालु इन तीर्थों के दर्शन आसानी से कर सकेंगे। आगामी समय में वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र तक इसका विस्तार किया जिससे वाराणसी, विश्व्याचल और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी।

एग्जिट पोल पर प.बंगाल में घमासान

सनत जैन

पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एसआईआर से लेकर मतदान होने तक चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी तथा टीएमसी के बीच में लगातार टकराव देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है, उसकी चर्चा संपूर्ण भारतवर्ष में हो रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल तक मतदाता और टीएमसी अपनी लड़ाई लड़ रही है। ऐसी स्थिति इसके पहले कभी नहीं देखी गई। तार्किक विसंगित के नाम पर पश्चिम बंगाल में पहली बार चुनाव आयोग ने एक करोड़ से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर दिया था। उसके बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद अभी भी 62 लाख मतदाताओं को मतदान का अधिकार नहीं मिला। इसको लेकर पश्चिम बंगाल में पिछले कई महीने से मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीच में तनाव है। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल को लेकर जो नए-नए नियम बना रहा है। उसको लेकर भी बार-बार टीएमसी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़नी पड़ी है। चुनाव आयोग के मामले में न्यायपालिका ने न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी। उसके बाद भी मतदाता मतदान करने से वंचित रहे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। रही-सही कसर अब एग्जिट पोल के माध्यम से पूरी होती हुई दिख रही है। राष्ट्रीय चैनल और कुछ ऐसी सर्वे एजेंसी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में बना दी है। भाजपा को 190 सीटों पर जीत मिलने का दावा एग्जिट पोल में किया गया, जो जमीनी हकीकत के विपरीत है। पश्चिम बंगाल के दो बांला चैनलों ने भी एग्जिट पोल किया। उसमें 161 सीटें टीएमसी को और भाजपा को 71 सीटें तथा 49 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई गई। आनंद बाजार पत्रिका समूह के बांग्ला न्यूज चैनल ने टीएमसी को 177 से लेकर 187 सीटें मिलने का अनुमान बताया। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटें मिलने की संभावना जताई है। एग्जिट पोल में भारी अंतर होने तथा जमीनी हकीकत के विपरीत एग्जिट पोल आने से पश्चिम बंगाल में

घमासान शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर टीएमसी बार-बार सवाल खड़े करती रही है। ऐसी स्थिति में मतगणना के पहले टीएमसी ने फार्म 17 का रिकॉर्ड अपने सभी बूथ एजेंट से मंगा लिया है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के सभी बूथ में उपयोग में लाई गई ईवीएम मशीन, उनके सीरियल नंबर तथा शुरू और अंतिम मत संख्या का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर लिया है। मतगणना स्थल पर टीएमसी के सभी मतगणना एजेंटों को सूची उपलब्ध कराई है। वहीं बार पश्चिम बंगाल में इस तरह की तैयारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने की है। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप टीएमसी हर स्तर पर लगाती आ रही है। ऐसी स्थिति में मतगणना के दौरान टीएमसी के एजेंट किसी भी किस्म की गड़बड़ी रोकने के लिये सजग होंगे। एग्जिट पोल ने एक तरह से मतगणना के पहले आग में घी डालने का काम किया है। भाजपा और चुनाव आयोग को लेकर टीएमसी आक्रामक है। वहीं ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर चुनाव आयोग और भाजपा आक्रामक है। ऐसी स्थिति में मतगणना के दौरान और मतगणना के पश्चात किस तरह के हालात प. बंगाल में बनेंगे, इसको लेकर अभी से तरह-तरह की चिंता व्यक्त की जाने लगी है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का गांव-गांव तक केंडर है। इस बार टीएमसी ने भाजपा चुनाव आयोग से लड़ने की पूरी तैयारी की है। ऐसी स्थिति में मतगणना के दौरान चुनाव आयोग को सजग होने की जरूरत है। गड़बड़ी होने की स्थिति में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति स्थिति बनी रहे। चुनाव आयोग ने अभी तक बूथ-विधानसभा में हुए मतदान के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किये हैं। जिसके कारण चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर राजनैतिक दलों का चुनाव आयोग पर विश्वास खत्म होता जा रहा है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ सभी दलों के साथ सहयोग करेगा। तभी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ेगी। चुनाव आयोग पूर्व की भांति मतदाता सूची से लेकर मतदान और मतगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करना आवश्यक है। चुनाव आयोग को गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है।

बंगाल में लोकतंत्र पर हमला और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल

कान्तिराल मांडोत

पश्चिम बंगाल में चल रहे चुनावी परिदृश्य ने एक बार फिर भारतीय लोकतंत्र के सामने गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जिस प्रक्रिया को संविधान ने जनता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति का माध्यम माना है, उसी प्रक्रिया के दौरान हिंसा, मारपीट, डराने-धमकाने और चुनावी मशीनों से छेड़छाड़ जैसे आरोप सामने आना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। हाल के घटनाक्रमों में भाजपा कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों पर हमले, बूथों पर तनाव और ईवीएम के साथ कथित छेड़छाड़ की खबरें इस बात का संकेत देती हैं कि चुनाव केवल मतदान का कार्य नहीं रह गया है बल्कि शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बनता जा रहा है।

इन घटनाओं के केंद्र में राजनीतिक दलों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि क्या मतदाता वास्तव में बिना भय के अपना मतार्थिकार इस्तेमाल कर पा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। यह स्थिति केवल राजनीतिक टकराव नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा है।

चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से बूथ स्तर पर एजेंटों को निशाना बनाया गया, उम्मीदवारों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और खुलेआम मारपीट हुई, वह यह दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि हर नागरिक बिना किसी दबाव के अपने मत का प्रयोग करे। लेकिन जब किसी पोलिंग एजेंट को घायल कर दिया जाता है या किसी उम्मीदवार को मतदान केंद्र के आसपास घेर लिया जाता है, तो यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर आघात है।

सबसे गंभीर आरोप ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ को लेकर सामने आए हैं। यदि किसी भी मतदान केंद्र पर किसी विशेष पार्टी के चुनाव चिन्ह के सामने टेप लगाया जाता है, तो यह केवल तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि मतदाता की स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास माना जाएगा। इस प्रकार की घटनाएं



लोकतंत्र की आत्मा के विपरीत हैं। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जहां भी ऐसी शिकायतें सही पाई जाएंगी, वहां पुनर्मतदान कराया जाएगा। यह कदम आवश्यक है, लेकिन इससे यह सवाल भी उठता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही क्यों हुई।

राजनीतिक बयानबाजी भी इस पूरे माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना रही है। ममता बनर के नेतृत्व वाली सरकार पर विश्वस लगातार आरोप लगा रहा है कि राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। वहीं सत्तधारी दल इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताकर खारिज करता है। इस आरोप-प्रत्यारोप के बीच असली मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है, जो है आम मतदाता की सुरक्षा और स्वतंत्रता।

चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह जनता के विश्वास का प्रतीक होता है। यदि इस प्रक्रिया में हिंसा और डर का माहौल हावी हो जाए, तो यह विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। पश्चिम बंगाल में सामने आई घटनाएं यह संकेत देती हैं कि राजनीतिक दलों को आत्मसंयम करने की आवश्यकता है। किसी भी दल की जीत या हार से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र केवल संस्थाओं से नहीं चलता, बल्कि उसमें भाग लेने वाले सभी पक्षों की जिम्मेदारी होती है। राजनीतिक दलों, प्रशासन, सुरक्षा बलों और मतदाताओं सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव एक उत्सव की तरह संपन्न हो, न कि संघर्ष के मैदान की तरह। जब कार्यकर्ता हिंसा का सहारा लेते हैं, तो वे अपने ही लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करते हैं।

मोहन लाल

जीवन के संघर्षों में भी अडिग रहना संघ से सीखा। छुटपन में संघ शाखा ने जो सिखाया, उसका चेतनावचेतन में यह प्रभाव बना रहा। किसी भी संगठन को इतना व्यापक, विशाल, सक्रिय, अनुशासित बने रहना उसके लिए सौ वर्ष कोई मायने नहीं रखते। इन सौ वर्षों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने ध्येय पर खड़ा रहा कि भारत एक ‘हिंदू राष्ट्र’ है। संघ की हिंदू राष्ट्र की परिभाषा भी बड़ी विशाल है। इस देश का प्रत्येक सम्प्रदाय जो भारत की धरती को अपनी मातृभूमि, पितृ भूमि मानता है वह हिंदू है। इसमें तनिक संकीर्णता नहीं। यह हिंदू राष्ट्र की विडम्बना है कि अंग्रेजों ने इस राष्ट्र को विभाजित कर दिया। अन्यथा म्यांमार व बांग्लादेश और पाकिस्तान इसी में तो थे। आज भी सही मुसलमान यही कहेंगा कि हमारे पुरखे हिंदू थे। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला तो संघ से कहते हैं कि हमारे दादा-पड़दादा हिंदू ब्राह्मण थे। मुझे गर्व है कि मैं संघ परिवार का एक छोटा-सा घटक हूं। ‘हिंदू-मुस्लिम’ एकता बिन स्वराज्य नहीं। किसी भी संगठन की आत्मा है कि वह किस सीमा तक अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दे सकता है कि वह अपने संगठन और उस संगठन के विचारों और मूल्यों पर खड़ा रहे। संघ और उसका स्वयंसेवक विचारों और मूल्यों पर इन सौ वर्षों में अडिग रहा। यही ‘मानव स्वयंसेवक’ राष्ट्र की कायाकल्प का समुच्च साधन है। मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक ‘गुरु’ गोलवलकर को निकट से देखने का अवसर मिला। ठाकुर राजेंद्र सिंह जी, माननीय बराला साहिब देवसर, के. सुदर्शन जी और वर्तमान सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत के दर्शनों और उन्हें निकट से देखने के कई अवसर मिले। मुझे गर्व है कि मुझे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवानी, बलराज मधोक, दीन दयाल

देशसेवा व सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित संघ

उपाध्याय, मुरली मनोहर जोशी, केदारनाथ साहनी जैसे सर्वश्रेष्ठ संघ प्रचारकों का आशीर्वाद मिला। प्रचारकों का जीवन बड़ा कठिन हुआ करता था। 20-20 किलोमीटर साइकिल चलाकर संघ शाखाओं का विस्तार करना, नए-नए स्वयंसेवकों, संघ शिक्षा वर्गों द्वारा नए-नए विस्तारक, प्रचारक संघ के लिए खड़े करना उनका मुख्य उद्देश्य था। पर यह सब कुछ हसते-हंसते करना है। प्रत्येक वर्ष मई-जून के महीनों में, तपती गर्मी और लू में संघ शिक्षा वर्गों में ट्रेनिंग लेना, शूट-ब्राह्मण का एक ही स्थान पर भोजन करना, संघ वर्गों में ‘परिवार-मिलन’ के क्या उत्तम गुण वहां सिखाए जाते हैं। सफ़ेद कमीज, खाकी निकर, (अब पैंट), काली टोपी, काले बूट (फीतो वाले), खाकी जुगबें, हाथ में दंड, वेशभूषा से सजग स्वयंसेवक सचमुच भारत माता के रक्षक लगते हैं। कदम से कदम मिला कर ‘रूट मार्च’ निकालना दर्शकों को मुग्ध कर देता है। आज राष्ट्रीय स्वयसेवक संघ एक वट वृक्ष बन गया है। अगर आपको दुनिया का सबसे विशाल, सबसे संगठित संगठन देखने को मिलेगा तो वह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही होगा। इन सौ वर्षों में संघ के कई आलोचक हुए, कई संघ को गालियां भी देते रहे हैं। ऐसे वही लोग हैं, जिन्होंने संघ को निकट से देखा नहीं, संघ कैसे काम करता है, इसकी जांच तक नहीं की। मेरा निवेदन है कि संघ शाखाओं में आओ, ध्वज प्रणाम करो और ‘नमस्ते सादा वत्सले’ भारत मां की प्रार्थना करें और अपने-अपने काम धंधे में लग जाओ। ‘समूचा राष्ट्र’ एक कुटुम्ब है। संघ कट्टरवाद, अलगाववाद को देश के लिए जहर मानता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्मांतरण को सबसे बड़ा शत्रु समझता है। यह एक ‘दैवी संगठन’ है। समाज को जोड़ना, उसमें समन्वय बनाए रखना, यही संघ विरोधियों को पचता नहीं है। हमने जो कुछ सीखा, संघ से सीखा। यह भी संघ से ही सीखा कि अपने से छोटे कार्यकर्ता को अपने से आगे रखो।

आखिर क्यों बिखरे हैं आप के नेता?

गुंजा कपूर

भारतीय राजनीति के हालिया घटनाक्रम को देखते हुए एक बात बार बार मन में आती है कि आखिर लोग किसी नेता के साथ क्यों जुड़ते हैं और कब उससे दूरी बना लेते हैं? राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी से अलग होने की चर्चाओं के बीच यह सवाल और भी प्रासंगिक हो गया है।

हम अक्सर ऐसे मौकों पर बहुत आसान निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कभी इसे अवसरवाद कह देते हैं, कभी संगठन की कमजोरी, और कभी एजेंसियों के डर का हवाला दे देते हैं। लेकिन सच यह है कि राजनीति को इस तरह समझना उसे बहुत संकीर्ण कर देगा। राजनीति दरअसल विश्वास और प्रेरणा की निरंतर प्रक्रिया है।

2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 240 सीटों पर आकर रुकी। यह पूर्ण बहुमत से कम था, लेकिन सरकार फिर भी बनी और विपक्ष ने भी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही थी कि अब राजनीतिक आकर्षण बटेगा, लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। पर जो हो रहा है, वह थोड़ा अलग है।

विपक्ष से निकलने वाले लोग किसी दूसरे विपक्षी दल या एनडीए के घटक दल में जाने के बजाय भाजपा की ओर जा रहे हैं। यह केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, यह उस भरोसे का संकेत है जो कहीं न कहीं बन रहा है। विपक्ष में आज ऊर्जा की कमी नहीं है। राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, अभिषेक बनर्जी हैं, हेमंत सोरेन हैं, रेवंत रेड्डी हैं, के. कविता हैं, आदित्य ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, सब अपेक्षाकृत युवा, सक्रिय और अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी। फिर भी यदि प्रवाह एक ही दिशा में दिखता है, तो यह मानना पड़ेगा कि केवल युवा होना या पद पर होना पर्याप्त नहीं है। कुछ और है जो लोगों को खींचता है, और वह है प्रेरणा।

यह भी ठीक नहीं है कि हर बदलाव को केवल लाभ हानि के तराजू पर तौल दिया जाए। कपिल मिश्रा लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में अपेक्षित भूमिका से दूर रहे, उसके बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली। आर.पी.एन. सिंह जैसे नेताओं



को भी तत्काल कोई बड़ी राजनीतिक उछाल नहीं मिली। जयवीर शेरिलाल जैसे युवा चेहरे भी बिना किसी त्वरित लाभ के भाजपा में आए। फिर भी इन सबने दिशा बदली। इसका अर्थ है कि राजनीति में निर्णय केवल ताल्कालिक लाभ से संचालित नहीं होते, उसके पीछे एक गहरा भरोसा और एक दृष्टि होती है।

यहां एक और बात समझनी जरूरी है। आज जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, खासकर जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास विकल्प हैं। वे चाहें तो अच्छी नौकरी कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अपने लिए सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन बना सकते हैं। अगर वे राजनीति में आते हैं, तो इसलिए कि उन्हें लगता है कि यहां वे कुछ सार्थक कर पाएंगे। लेकिन अगर उन्हें बार बार समझौता करना पड़े, अपने मूल्यों से हटना पड़े, तो उनके लिए यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि फिर राजनीति में रहकर क्या हासिल करना है? ऐसे लोग बिना ज्यादा शोर किए वापस अपने रास्ते पर लौट जाते हैं। इसलिए शिक्षित और सक्षम युवाओं को साथ बनाए रखना किसी भी नेतृत्व के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है।

यहीं पर नेतृत्व की असली कसौटी सामने आती है। नरेंद्र मोदी की बात इसलिए अलग दिखती है क्योंकि वह लोगों से जुड़ने की एक सहज क्षमता रखते हैं। जब वह किसी लिट्टी चोखा बेचने वाले से बात करते हैं, किसी नाविक से बातचीत करते हैं, या उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पाने वाली महिला से यह पूछते हैं कि अब

उसका जीवन कितना बदला है, तो वह संवाद बनावटी नहीं लगता। वह सामने वाले के जीवन को समझने की कोशिश करते हैं और उसी स्तर पर बात करते हैं। यही वह क्षण होता है जब दूरी खत्म होती है और भरोसा बनता है। युवाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी न तो युवाओं की तरह बोलते हैं, न उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, न उनकी भाषा या अंदाज अपनाते हैं, फिर भी युवा उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि युवा केवल शैली नहीं, बल्कि स्थिरता और स्पष्टता देखते हैं।

उन्हें ऐसे नेता चाहिए जो निर्णय ले सके और उन पर टिक की सके; जो कठिन समय में डामगाएं नहीं।

यही दृढ़ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी दिखती है। साधारण प्रष्ठभूमि से आए, बिना पारिवारिक राजनीतिक विरासत के, और फिर भी अपने कार्यों और निर्णयों के कारण युवाओं के बीच एक अलग तरह का विश्वास स्थापित किया है। जनता या नेता को प्रेरित करने के लिए उनके जैसा दिखना या बोलना आवश्यक नहीं है। नेतृत्व अपने आचरण और निर्णयों से पहचाना जाता है। प्रेरणा केवल एक दल तक सीमित नहीं रही है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, तो उनकी युवा ऊर्जा ने एक पूरी पीढ़ी को आकर्षित किया। इंदिरा गांधी ने 1971 में जिस दृढ़ता का परिचय दिया, उसने पूरे देश को, विशेषकर युवाओं को, उनके साथ खड़ा कर दिया। इतिहास बार बार यही बताता है कि जब नेतृत्व भरोसा और दिशा देता है, तो लोग साथ आते हैं।

अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। उन्होंने एक समय लोगों को यह भरोसा दिलाया कि राजनीति बदली जा सकती है और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन प्रेरणा को बनाए रखना पड़ता है। जिस दिन यह कम होने लगती है, उसी दिन लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं।

इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह उस प्रेरणा को निरंतर जीवित रखे, जो जनता और नेता, दोनों को उसके साथ जोड़े रखे।

क्या करें जब आर नाक से खून



नाक से खून आने की समस्या गर्मियों में ज्यादा बढ़ जाती है। नाक के बीच की हड्डी के आगे के भाग में खून की कई नसें आपस में मिलकर एक जाल-सा बनाती हैं, जिसे लिटल्स एरिया- कहते हैं। अधिकतर मरीजों में नाक से खून इसी जगह से ज्यादा आता है। सांस लेने में गर्म हवा जब इस भाग से टकराती है, तो वहां पर सूखापन आ जाता है और पपड़ी पडने लगती है। जैसे ही जब कोई व्यक्ति इस पपड़ी को नाक में उंगली डालने की आदत के कारण निकालता है, तब खून निकलने लगता है।

कुछ प्रमुख कारण

- बहुत गर्म वातावरण में रहना।
- हाई ब्लडप्रेशर में भी नाक से खून आता है।
- नाक में चोट लगना।
- नाक में कोई बाहरी चीज चली जाए।
- नाक में किसी तरह का संक्रमण होना,
- बैक्टीरिया या वाइरस का प्रकोप।

प्राथमिक उपचार

- मरीज को बठाकर उसकी नाक के अगले हिस्से को कुछ मिनट के लिए दबाकर रखना चाहिए। दबाव पड़ने से खून रुक जाता है।
- नाक पर बर्फ रखें।
- जब खून निकल रहा हो, उस वक्त मरीज को लिटाना नहीं चाहिए। इससे खून गले से होकर पेट में जाने लगता है और मरीज को उल्टियां व पेट में दर्द हो सकता है। ज्यादातर मरीजों में प्राथमिक उपचार के बाद रक्त आना बंद हो जाता है। यदि खून आना बंद न हो या बार- बार आए, तो किसी नाक, कान व गला विशेषज्ञ से परामर्श लें ताकि खून आने की वजह का पता लगाया जा सके। विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा खून रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं।

ध्यान दें

गर्मियों के मौसम में चिलचिलाती धूप से निकलकर सीधे एयर कंडीशन वाले कमरे में या फिर कुलर वाले कमरे में न जाएं। थोड़ी देर रुकने के बाद ही कमरे में प्रवेश करें।

आज के समय प्रदुषण इतना बढ़ गया है कि लोगों को त्वचा संबंधी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सब लोग चाहते हैं कि उनकी त्वचा देखने में अच्छी और अट्रैक्टिव दिखाई दे। कई वजह से आपको चेहरे पर भारीपन लगता है। लोग चाहते हैं कि त्वचा पर कुछ ऐसा लगाएं जिससे उनकी स्कीन में फेशनेस लगे। सभी लड़कियां यही चाहती हैं कि उनके पास कुछ ऐसा हो जिससे उनको आराम मिले और उनका चेहरा चमक उठें। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे आप अपनी स्कीन को फ्रेश कर सकते हैं। ये सभी चीजें प्राकृतिक होंगी, जो आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। इन चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा को फ्रेश कर सकते हैं।

बनाएं अपनी त्वचा को फ्रेश



वर्फ का पानी: फ्रीजर में से चिल्ड वॉटर निकालकर उससे चेहरा धो लें। इससे आपको फ्रेशनेश आवश्यक मिलेगी। यह सबसे सस्ता स्कीन टोनर है, जो आपकी त्वचा को मिनट भर में ही फ्रेश कर देता है।

दूध: फ्रिज में रखे हुए दूध को निकालकर उससे चेहरे को धो लें या कॉटन बॉल में लगाकर चेहरे को साफ कर लें। इससे चेहरे के छिद्र खुलने के साथ साथ आपके चेहरे पर प्राकृतिक चमक आ जाएगी।

गुलाब जल: गुलाब जल बहुत सस्ता होता है और घरों में आसानी से मिल जाता है। इसमें एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं जो चेहरे पर पिंपल नहीं होने देते । गुलाब जल से स्कीन को कोई नुकसान नहीं होता।

ग्रीन टी: ग्रीन टी के तत्व चेहरे के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ग्रीन टी को पानी के साथ मिलाकर चेहरा धोने से आपको अच्छ महसूस होगा। इससे चेहरे में चमक आ जाएगी।

एलोवेरा जूस: चेहरे के लिए एलोवेरा के पत्तों का गूदा बहुत फायदेमंद होता है। इसके पत्तों का रस भी चेहरे के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसको चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ तो होता ही है, दमकने भी लगता है। प्रतिदिन सोने से पहले इसको चेहरे पर लगाने से आपका चेहरा शाहन करने लगेगा।

ब्रेन ट्यूमर अब नहीं रहा लाइलाज

मस्तिष्क ट्यूमर (ब्रेन ट्यूमर) मस्तिष्क में या मस्तिष्क के किसी भाग में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि से संबंधित रोग है। ये असामान्य कोशिकाएं मस्तिष्क में एक गांठ के रूप में बन जाती हैं। ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा रोग है, लेकिन आधुनिक मेडिकल साइंस में हुई प्रगति के कारण अब समय रहते इस रोग का इलाज संभव है.... ब्रेन ट्यूमर के कई प्रकार हैं। जो ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में ही उत्पन्न होते हैं, उन्हें प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। वहीं जो ट्यूमर शरीर के अन्य भागों से शुरू होकर मस्तिष्क तक भी फैल जाते हैं, उन्हें मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर कैंसर रहित होते हैं, जिन्हें बिनाइन कहा जाता है और कुछ ब्रेन ट्यूमर कैंसर ग्रस्त होते हैं, जिन्हें मैलिग्नेंट (घातक) कहा जाता है। अलग-अलग प्रकार के ब्रेन ट्यूमर की वृद्धि की रफ्तार अलग-अलग होती है। प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर अनेक तरह के होते हैं। जैसे...

ग्लीओमा

ये ट्यूमर मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी से शुरू होते हैं। एकास्टिक न्यूरोमा कैंसर रहित (बिनाइन) ट्यूमर हैं, जो शारीरिक संतुलन और सुनने की शक्ति को संचालित करने वाली तंत्रिका (नर्व) पर विकसित होते हैं।

पिट्यूटरी एडेनोमा

ये ज्योदातर बिनाइन ट्यूमर होते हैं और इनमें से ज्यादातर मस्तिष्क के आधार पर स्थित पिट्यूटरी ग्रंथि में विकसित होते हैं। ये पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन को प्रभावित कर सकते हैं और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है।

मेडुलोब्लास्टोमा

ये बच्चों में होने वाले सबसे सामान्य किस्म के कैंसरजन्य मस्तिष्क ट्यूमर हैं। वयस्ककों ये ट्यूमर होते हैं।

जर्म सेल ट्यूमर

ऐसे ट्यूमर बचपन से ही विकसित होते हैं। ऐसे कैंसर मस्तिष्क के अलावा शरीर के अन्य भागों पर शुरू होते हैं, लेकिन बाद में मस्तिष्क को अपनी चपेट में ले लेते हैं। जोखिम वाले कारण उम्र- ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ती उम्र से संबंधित है। उम्रदराज लोगों में ब्रेन ट्यूमर अधिक होते हैं। हालाँकि कुछ किस्म के ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकते हैं।

विकिरण से संपर्क

कुछ प्रकार के विकिरण (रेडिएशन) के संपर्क में आने वाले लोगों में ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है।

पारिवारिक इतिहास

कुछ किस्म के ब्रेन ट्यूमर ऐसे लोगों में होते हैं, जिनके परिवार में ब्रेन ट्यूमर या नेनेटिक बीमारियों



का इतिहास रहा हो।

डायग्नोसिस

इसके अंतर्गत एमआरआई, कंप्यूट्राइड टोमोग्राफी (सीटी) स्कैन और पेट स्कैन शामिल हैं। शरीर के अन्य भागों में कैंसर का पता लगाने के लिए भी परीक्षण कराए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर फेफड़े के कैंसर का पता लगाने के लिये सीने का सीटी स्कैन।

वहीं बायोप्सी परीक्षण भी कराया जाता है। सुई का इस्तेमाल करके भी बायोप्सी की जा सकती है। बायोप्सी से लिए गए नमूने का परीक्षण माइक्रोस्कोप के जरिए

किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि यह कैंसरजन्य है या कैंसररहित। यह जानकारी डायग्नोसिस और रोग के इलाज के लिये महत्वपूर्ण है।

इलाज

ब्रेन ट्यूमर का उपचार ट्यूमर के प्रकार, आकार और स्थान पर निर्भर करता है। जैसे... सर्जरी अगर ब्रेन ट्यूमर ऐसे स्थान पर है, जहां तक ऑपरेशन के लिए सुलभता से पहुंचा जा सकता है, तब न्यूरो सर्जन ब्रेन ट्यूमर के यथासंभव अधिक से अधिक हिस्से को हटाने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए की

स्वस्थ रखता है केला

केला खाने में स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें थाइमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और फॉलिक एसिड पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। एक शोध से पता चला है कि केला खाने से स्वास्थ्य सही रहता है। साथ यह सुंदरता भी बढ़ाता है। केला खाने से न केवल शारीरिक क्षमता बढ़ती है, बल्कि मासिक धर्म के समय होने वाली समस्याओं से भी राहत मिलती है। शुरुार और

फाइबर से भरपूर होने के साथ ही केला कई बीमारियों से बचाता है। इसके कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार हैं।
केला ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। यह एक ऐसा फल है जिसको खाने पर तुरंत एनर्जी मिलती है। यह तनाव कम करने में भी मददगार है। इसमें ट्राइप्टोफान नामक एमिनो एसिड होता है जिससे मूड सही होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे अनेक तत्वों के कारण यह डिप्रेशन जैसी कई बीमारियों को दूर रखने में कारगर है। दिल के मरीजों के लिए भी केला बहुत फायदेमंद होता है। पोटेशियम



है कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है तो केले का सेवन करना शुरू कर दें। केला याददाश्त बढ़ाने में काफी सहायक होता है।

से भरपूर इस फल में नमक की मात्रा कम होती है जिसके कारण यह उच्च रक्तचाप में फायदेमंद साबित होता है। यदि आपको लगता



समोसे को बोलें बाय सलाद को कहें हाय

जब भी हम तनाव में होते हैं या कुछ खाए काफी देर हो जाती है तो तेज भूख लगती है। पहली इच्छा कुछ सेहतमंद चीज खाने की जगह एक्स्ट्रा चीज वाले पिज्जा, समोसा या फिर क्रीमयुक्त पेस्ट्री खाने की होती है। बहुत कम ही लोग होते हैं, जिसने तनाव की स्थिति में खाने की इच्छा होने पर उसने सलाद या फल खाना चाह हो।

ऑफिस में लेट हो जाएं

ऐसी स्थिति में लो फेट दूध से बनी कोल्ड कॉफी और गेहूं से बना सैंडविच खाएं। इसमें सोया और चीज फिलिंग कर सकते हैं। तनाव की स्थिति में सेरोटोनिन रसायन कम हो जाता है। दूध में प्रोटीन होता है। सैंडविच से आपको प्रोटीन और कॉम्लैक्स कार्बोहाइड्रेट दोनों मिल जाते हैं, जिससे आप एलर्ट रहते हैं। पर, ध्यान रहे, अधिक कॉफी तनाव बढ़ा भी सकती है।

नींद नहीं आती हो

दलिया और केला खाएं। तनाव नींद बढ़ाने वाले हॉर्मोन मेलाटोनिन से कम हो जाता है। मेलाटोनिन जई, मक्का, ब्राउन राइस, अदरक, पका टमाटर, सोया और खजूर आदि में होता

है। दलिया, दूध के साथ खाएं। इससे कॉम्लैक्स कार्बोहाइड्रेट और फाइबर दोनों मिलते हैं। यह मस्तिष्क पर असर करता है, आप अच्छी नींद ले पाते हैं। केले में मेलाटोनिन और मैग्नीशियम दोनों होते हैं। मैग्नीशियम प्राकृतिक तरीके से मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। रात को सहज नींद आ जाती है।

इंटरव्यू के दौरान

ग्रीन सलाद खाएं। शाकहारी हैं तो इसमें सोयाबीन, अलसी के बीज और अखरोट की गिरी मिला सकते हैं। मांसाहारी ग्रिल्ड चिकन या सैलमन मछली ले सकते हैं। ग्रीन सलाद विटामिन बी-12 का अच्छा स्रोत है। इससे मूड अच्छ करने वाले सेरोटोनिन और डोपामाइन रसायन मिलते हैं, जिसकी कमी से थकावट और झुंझलाहट होती है।

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण (हेट स्पीच) देने के मामले में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को बड़ी राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इन नेताओं के बयानों से प्रथम दृष्टया कोई भी संज्ञेय अपराध बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है। अनुराग ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि प्रवेश वर्मा दिल्ली की राजनीति में सक्रिय प्रमुख चेहरा हैं।

यह पूरा विवाद शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समय का है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) की नेता वृंदा करात और के.एम. तिवारी ने आरोप लगाया था कि जनवरी 2020 में चुनावी रिलियों के दौरान अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा ने अत्यंत भड़काऊ भाषण दिए थे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी।

मिशन पंजाब: अमित शाह संभालेंगे कमान



चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल के मैराथन चुनावी अभियान के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब की राजनीति पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने मिशन पंजाब का खाका तैयार किया है, जिसके तहत अमित शाह अब चुनाव होने तक हर महीने राज्य का दौरा करेंगे। इस बार भाजपा की चुनावी रणनीति के केंद्र में ड्रास का मुद्दा रहने वाला है। बताया जा रहा है कि मई महीने से ही पंजाब में नशे के खिलाफ एक व्यापक अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसकी कमान स्वयं अमित शाह संभालेंगे। इस अभियान के अंतर्गत पूरे राज्य में जागरूकता यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनमें समय-समय पर केंद्र और राज्य स्तर के दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में सत्ता में होने के कारण भाजपा वहां मजबूत स्थिति में है।

युद्धपोत ‘महेंद्रगिरि’ 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से है लैस, नौसेना की ताकत में इजाफा



नई दिल्ली। पूरी तरह से स्वदेशी और अत्याधुनिक तकनीक से लैस युद्धपोत ‘महेंद्रगिरि’ को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इससे नौसेना की समुद्री ताकत में इजाफा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने इस युद्धपोत को तैयार किया है। नीलगिरि-श्रेणी का यह छठा युद्धपोत है। इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में ही हुआ है, जो ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान को मजबूती देता है। इसे दुश्मन की नजरों से बचने यानी स्टेल्थ क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। समुद्र में यह लंबे समय तक टिक सकता है और कई तरह के मिशन संभालने में सक्षम है। जानकारी के मुताबिक इस युद्धपोत को खास तौर पर खतरनाक बनाती हैं इसकी हथियार प्रणालियां। इसमें दूर तक मार करने वाली आठ ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं।

चुनाव आयोग पर कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप



नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान व्यापक स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत हैं। उन्होंने कहा, सिर्फ दो-चार जगहों पर अनियमितताएं नहीं हुई बल्कि पूरे बंगाल में हुई हैं। बंगाल और असम में जिस प्रकार से चुनाव हुआ वह लोकतंत्र पर कलंक है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने शनिवार को कहा कि गड़बड़ियां केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित नहीं हो पाया। उनके अनुसार, करीब ढाई लाख केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद जिस तरह की घटनाएं सामने आईं।

भारत दुनिया के सबसे बड़े नमक उत्पादकों में से एक

नई दिल्ली। आजकल सोशल मीडिया पर नमक की अनोखी सफेद खेती के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। दर्शक इन वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हैं कि कैसे समुद्र के खारे पानी को बड़े-बड़े मैदानों में फैलाकर सुखाया जाता है और फिर चमकती हुई सफेद नमक के अंदर यहाँ की नमक की खेती एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में गुजरात का कच्छ का रण, राजस्थान का सांभर झील इलाका और तमिलनाडु के समुद्री किनारे नमक की खेती के प्रमुख केंद्र हैं। इन स्थानों पर बड़े-बड़े मैदान बनाए जाते हैं जिन्हें ‘सांल्ट पैन’ या नमक के खेत कहते हैं। ये खेत समुद्र से थोड़ा ऊंचे या नीचे स्तर पर होते हैं ताकि पानी आसानी से आ और जा सके। स्थानीय मछुआरे या किसान समुद्र के खारे पानी को इन मैदानों में भरते हैं, और फिर शुरू होती है तेज धूप और शुष्क हवा की मेहनत।

मतगणना मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए, इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे।

यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस



नरसिम्हा और जस्टिस जाँयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जाँयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि कार्डिंग सुपरवाइजर और कार्डिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी। कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है। जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे।

टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए। सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे। टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है।

वकील सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता, तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि मगणना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है।

चुनाव प्रक्रिया पर शक करने वालों को स्पष्ट संदेश : भाजपा

पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट के इनकार ने चुनाव प्रक्रिया पर शक पैदा करने की कोशिशों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने शनिवार को यह बात कही। शीर्ष कोर्ट ने शनिवार को कहा, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की उस याचिका पर किसी और आदेश की जरूरत नहीं है, जिसमें उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मियों की तैनाती संबंधी चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। भाजपा नेता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और कानूनी झटका देते हुए दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी से बाहर रखने को चुनौती दी थी। तत्काल सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई से इनकार यह स्पष्ट संदेश देता है कि मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने या उस पर शक करने कोशिशों को आसानी से मान्यता नहीं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह ममता बनर्जी के लिए एक और न्यायिक झटका है। मालवीय की टिप्पणी पर टीएमसी की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जाँयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा, चुनाव आयोग को मतगणना कर्मियों को चुनने का अधिकार है और 13 अप्रैल का उसका आदेश गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने कहा कि सर्कुलर में साफ है कि केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों का मिश्रण होगा और तृणमूल कांग्रेस की किसी गड़बड़ी की आशंका गलत है। आयोग ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि सर्कुलर को पूरी तरह लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में हुआ था। मतगणना चार मई को होगी।



तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाने की मांग की

नईदिल्ली। खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और संभावित युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है, जिसका सीधा असर भारत की सरकारी तेल विपणन कंपनियों पर पड़ा है। हालांकि ये अभी भी वैध मुद्दा हैं कि कंपनियों ने सरकार से पेट्रोल-डीजल और घरेलू एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग की है। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 126 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया, जिससे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों का घाटा और बढ़ गया है। यह स्थिति मुख्य रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर बढ़ी अनिश्चितता के कारण बनी है, जो दुनिया के सबसे अहम तेल आपूर्ति मार्गों में से एक है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से ओएमसी कंपनियों को पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और विमान ईंधन की बिक्री पर भारी नुकसान हो रहा है।

2000 रुपए के नोटों को लेकर आरबीआई ने दिया अपडेट

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपए के नोटों की वापसी को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आरबीआई ने मई 2023 में इन नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि ये अभी भी वैध मुद्दा हैं लेकिन इनका सामान्य लेन-देन में उपयोग लगभग बंद हो चुका है और लोगों को इन्हें बैंक में जमा करना पड़ रहा है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार, उस समय चलन में मौजूद 3.56 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोटों में से अब तक 98.47% नोट वापस आ चुके हैं। 30 अप्रैल 2026 तक यह राशि घटकर लगभग 5,451 करोड़ रुपए रह गई है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि 2000 रुपए के नोट अभी भी वैध मुद्दा हैं यानी इन्हें कानूनी रूप से रखा या जमा किया जा सकता है लेकिन इनका रोजमर्रा के लेन-देन में इस्तेमाल लगभग समाप्त हो चुका है।

एलपीजी सिलेंडर की किल्लत खत्म होने के आसार

नईदिल्ली। मीडिल ईस्ट टेंशन के बीच भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। स्ट्रैट ऑफ होर्मुज में बाधित जहाजों की आवाजाही के बीच ‘सर्व शक्ति’ नाम का एक बड़ा गैस टैंकर हजारों टन एलपीजी लेकर भारत की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इसके सुरक्षित पहुंचने से देश में एलपीजी की कमी काफी हद तक कम हो सकती है। यह टैंकर करीब 45,000 टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लेकर होर्मुज स्ट्रेट को क्रॉस करने की तैयारी में है। बता दें कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का उपयोग भारत में मुख्य रूप से घरेलू रसोई ईंधन के रूप में होता है। मौजूदा हालात में, जब स्ट्रैट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरान से जुड़े तनाव के कारण जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है, ऐसे समय में इस टैंकर का भारत आन बेहत राहत की उम्मीद जगा दी है।

इंडिगो को बड़ा झटका, मई में 17% सीट क्षमता घटी

नईदिल्ली। विमानन कंपनी इंडिगो मई महीने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सीट क्षमता में फरवरी के मुकाबले 17 प्रतिशत तक की कटौती कर रही है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण हवाई यातायात में लगातार आ रही रुकावटों की वजह से ऐसा किया जा रहा है। वैश्विक विमानन परामर्श फर्म ओएजी के आंकड़ों और विश्लेषण के अनुसार खाड़ी देशों से बाहर वाली विमानन कंपनियों में से इंडिगो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। हालांकि ओएजी के अनुसार इस बात की उम्मीद है कि विमानन कंपनी फरवरी के स्तरों की तुलना में जून (1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी) और जुलाई (1.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी) के दौरान अपनी क्षमता में थोड़ा-सा सुधार करेगी। यह उम्मीद इस अनुमान पर आधारित है कि एटीएफ के दाम मुफीद हो जाएंगे।

स्टो प्रमुख समाचार

पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला आज

अहमदाबाद। पिछले मैच में पंजाब किंग्स का



जीत का सिलसिला टूट गया और वह लगातार तीसरी जीत हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध गुजरात टाइटंस के खिलाफ

रविवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में अपने अभियान को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करेगा। राजस्थान रॉयल्स ने इस सप्ताह के शुरू में पंजाब किंग्स के अजेय अभियान पर रोक लगा दी थी। हालांकि पंजाब किंग्स की टीम आठ मैचों में 13 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी हुई है, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी), सनराइजर्स हैटाराबाद और राजस्थान रॉयल्स उससे सिर्फ एक अंक पीछे हैं। लगातार छह जीत हासिल करके शुरुआती बढ़त बनाने वाली पंजाब किंग्स की गेंदबाजी विभाग को लेकर कुछ चिंताएं हैं। पंजाब के बल्लेबाजों की तरह उसके गेंदबाज अपने प्रदर्शन में निरंतरता नहीं बना पाए हैं। उसके बल्लेबाजों के अच्छे प्रदर्शन के कारण गेंदबाजों की कमियां खुलकर सामने नहीं आई हैं लेकिन टूर्नामेंट अब महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है और ऐसे में कोई कमजोरी टीम पर भारी पड़ सकती है। गेंदबाजों की असफलता के कारण पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि या तो उन्हें बड़े लक्ष्य हासिल करने पड़ रहे हैं या फिर पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाना पड़ रहा है। ऐसे में पंजाब को अब अधिक स्पष्ट रणनीति के साथ मैदान पर उतरना होगा। पंजाब की फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही है और उसने कई कैच छोड़े हैं। टीम प्रबंधन को इस विभाग में भी काम करने की जरूरत है। हालांकि बल्लेबाजी अब भी पंजाब की सबसे बड़ी ताकत है। सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिम्पर सिंह ने अच्छी शुरुआत दी है, वहीं कूपर कोनोली ने भी रन बनाए हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाला मध्य क्रम मजबूत स्कोर बनाने या लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम साबित हुआ है।

मधुरेंद्र सिन्हा

वर्तमान की चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत ने निर्यात में नया कीर्तिमान बनाया है। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण भारत को यह उपलब्धि हासिल हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में हमारा कुल निर्यात 860 अरब डॉलर से अधिक हो गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें वस्तु और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं आयात में लगभग 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अंतरिम आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान वस्तुओं का कुल निर्यात लगभग 441 अरब डॉलर रहा।

भारत का यह प्रदर्शन और भी शानदार होता, यदि ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू नहीं हुआ होता। इस युद्ध का असर हमारे निर्यात

पर मार्च महीने में दिखाई दिया। उस महीने हमारे निर्यात में 7.6 प्रतिशत, यानी 59.6 अरब डॉलर की कमी आयी। अमेरिकी दबाव के कारण ईरान को भारत के निर्यात में लगातार गिरावट आती रही और यह 2018-19 के 17.03 अरब डॉलर से गिरते-गिरते महज 1.68 अरब डॉलर का रह गया है। लेकिन भारतीय निर्यातकों ने नये द्वार खोल लिये हैं। अगर वे ईरान की जगह संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात बढ़ा रहे हैं। कई अन्य देशों में भी भारत ने अपने पंख पसार दिये हैं। भारत ने पिछले दिनों ओमान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से व्यापार बढ़ाने के लिए समझौते किये हैं, जिसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा।

इंग्लैंड का बाजार बहुत बड़ा है और भारतीय निर्यातकों के लिए वहां काफी संभावनाएं हैं। भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीडीपी)



भारत का पहला मुक्त व्यापार समझौता था, जिसमें निवेशकों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से एक समर्पित प्रतिबद्धता शामिल है। यह भारत के निर्यातकों के लिए बड़ा रास्ता खोलता है। यूरोपीय संघ के देशों को बिना शुल्क निर्यात करने से हमारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग को न केवल आर्थिक लाभ हो रहा है, बल्कि उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। इस बीच, इस्राइल, कनाडा, जीसीसी देशों, चिली और पेरू के साथ चल रही व्यापार वार्ताएं विभिन्न क्षेत्रों में उच्च मूल्य वाले व्यापार गलियारों का विस्तार करने के भारत के दृढ़

संकल्प को दर्शाती हैं। भारत लगातार नये बाजारों की खोज करता जा रहा है और उसे उसमें सफलता भी मिल रही है।

मध्य-पूर्व में युद्ध के मद्देनजर भारत सरकार ने हाल ही में एक समय-सीमित ‘रिलीफ’ स्कीम अधिसूचित की है, जो निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत एक उपाय है और जिसे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। इसका उद्देश्य खाड़ी और पश्चिम एशिया समुद्री गलियारों में भू-राजनीतिक व्यवधानों से उत्पन्न निर्यात जोखिमों पर ध्यान देना है। इसीजीसी निर्यात के लिए महत्वपूर्ण जोखिम निवारण सहायता प्रदान करता है और देशभर में निर्यात से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण करने वाली व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईइएस) जैसी योजनाओं के साथ मिलकर काम करता है। भारत मुख्य रूप से परिकृत पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग

सामान, फार्मास्यूटिकल्स, रब एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान तथा मोबाइल फोन का बड़े पैमाने पर निर्यात करता है। इसके अतिरिक्त, भारत कृषि उत्पादों, वस्त्र, रसायन और प्लास्टिक के निर्यात में भी प्रमुख स्थान रखता है। भारत दवाओं का एक बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत का निर्यात भविष्य उज्ज्वल है और यदि ईरान-अमेरिका में समझौता हो जाता है, तो इसकी गति न केवल तेज होगी, बल्कि इसका असर हमारे कुल राजस्व पर भी पड़ेगा। हमें अपने आयात को भी नियंत्रित करना होगा। भारत के व्यापार घाटे का मुख्य कारण सोने का अबाध आयात है। भारत ने 2025-26 में कुल 721 टन सोने का आयात किया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की असाधारण रूप से बढ़ी हुई कीमतों के कारण भारत पर दबाव बढ़ गया है और उसका व्यापार घाटा ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है।

प्रदेश में डिजिटल जनगणना 2027 का शंखनाद

51 हजार से अधिक कर्मचारी घर-घर पहुँचकर जुटा रहे जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का फील्ड कार्य आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। 01 मई से शुरू हुआ यह महाभियान 30 मई 2026 तक चलेगा। इस कार्य के लिए राज्य भर में 51 हजार 300 प्रगणक और 9 हजार पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो घर-घर जाकर डेटा एकत्रित कर रहे हैं।

पहली बार डिजिटल जनगणना

इस बार की जनगणना ऐतिहासिक है क्योंकि यह पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है। प्रगणक मोबाइल ऐप के जरिए मकानों की स्थिति, परिवारों को उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित कुल 33 प्रश्नों की जानकारी दर्ज करेंगे।

अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्टवाई

प्रशासन ने जनगणना कार्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। रायपुर नगर निगम में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 44



कर्मचारियों को जनगणना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ सिविल आचरण नियमों के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना कार्य में बाधा डालना या इससे इनकार करना एक दंडनीय अपराध है।

उत्साह का वातावरण

दुर्गम क्षेत्रों में मिसाल- बस्तर जिले के तोकापाल तहसील अंतर्गत ग्राम गटाम

के प्रगणक ने विषम परिस्थितियों के बावजूद पहले ही दिन कार्य पूर्ण कर राज्य स्तर पर उत्साह का संचार किया। अभियान के पहले दिन ही जिला कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों ने फील्ड में जाकर कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया।

स्व-गणना राज्य में डिजिटल साक्षरता का प्रभाव दिखा, जहाँ 16 से 30 अप्रैल के बीच 1 लाख 49 हजार 862 परिवारों ने

वेब पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी गणना की।

सुरक्षा और गोपनीयता की गारंटी

जनगणना निदेशालय ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। यह जानकारी किसी भी टैक्स, पुलिस जांच या कोर्ट केस में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि सूचना का अधिकार के माध्यम से भी व्यक्तिगत डेटा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन आंकड़ों का उपयोग केवल राष्ट्र निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण हेतु किया जाएगा।

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जब भी प्रगणक उनके घर आएँ, उन्हें सही और सटीक जानकारी प्रदान करें। आपका यह सहयोग केवल जानकारी मात्र नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में आपका अमूल्य योगदान है।

निर्माण गुणवत्ता में जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी: मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत दाढ़ी क्षेत्र में हाल ही में निर्मित सीसी रोड के अल्प समय में ही क्षतिग्रस्त होने संबंधी प्रकाशित समाचार को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हिलाई या लापरवाही पूर्णतः अस्वीकार्य है।

मुख्यमंत्री साय ने बेमेतरा की कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई से दूरभाष पर चर्चा कर पूरे प्रकरण की विस्तृत एवं समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सीसी रोड का तकनीकी परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए तथा निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, कार्य की गुणवत्ता और पर्यवेक्षण व्यवस्था की समग्र जांच की जाए।



मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि यदि जांच में गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का त्वरित रूप से पुनर्निर्माण कर आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि जिले में संचालित अन्य निर्माण कार्यों की भी विशेष

समीक्षा की जाए, ताकि कहीं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की मूल ज़िम्मेदारी है, और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई अनिवार्य होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सतत मॉनिटरिंग, फील्ड निरीक्षण और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से विकास कार्यों की विश्वसनीयता एवं टिकाऊपन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनता का विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो सके। हमारी सरकार की मंशा स्पष्ट है – जनहित के प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाए।

सुशासन तिहार की सफलता से कांग्रेस त्यथित हुई : ठाकुर

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आयोजित सुशासन तिहार को मिल रहे अपार जन-समर्थन के मद्देनजर कहा है कि प्रदेश के कोने-कोने में जनता जिस उत्साह के साथ इस उत्सव से जुड़ रही है, उससे कांग्रेस खेमे में भारी खलबली मच गई है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि पिछले ढाई साल के पारदर्शी और जवाबदेह शासन का रिपोर्ट कार्ड है। महतारी वंदन योजना, किसानों को धान का बकाया बोनस और रामलला दर्शन जैसी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन ने कांग्रेस के झूठ के पुलिंदे को ढहा दिया है। श्री ठाकुर ने तंज कसते हुए कहा कि

कांग्रेस के नेता अब कुंठा में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। पाँच साल तक छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बनाने वाले आज सुशासन शब्द से ही घबरा रहे हैं और कांग्रेस को अपना अस्तित्व खतरे में नजर आने लगा है। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के शासन में कुशासन और कमिशनखोरी का बोलबाला था, जबकि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में आज अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुँच रहा है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि जनता को अब उनके खोखले नारों की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता मोदी की गारंटी और साय सरकार के सुशासन पर मुहर लगा चुकी है। सुशासन तिहार की सफलता कांग्रेस की राजनीतिक विदाई का स्पष्ट संकेत है।



छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

कांकेर में आईईडी ब्लास्ट की घटना दुःखद: दीपक बैज

रायपुर। कांकेर में माओवादियों के द्वारा लगाये गये आईईडी ब्लास्ट में एक इम्पेक्टर और तीन सिपाही शहीद होने की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा यह घटना बहुत दुःखद है, ईश्वर शहीद जवानों की आत्मा को शांति दे तथा उनके परिजनों को इस असौम दुःख को सहने की शक्ति दे। इस दुःखद घटना में जो जवान घायल हुए हैं उनका समुचित इलाज हो, ईश्वर उन्हें शीघ्र स्वस्थ करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि इस घटना से साफ हो रहा कि खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। नक्सलवाद एक ऐसा दंश है जिसे छत्तीसगढ़ विशेष तौर पर बस्तर के लोग लंबे समय से झेल रहे है। सरकार केवल हवाई दावे करके अपने कर्तव्य से मुंह न मोड़े। सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि अब वहां पर कोई और मौत नहीं हो। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे बस्तर में खतरनाक आईईडी प्रेशर बम जैसे न जाने कितनी घातक बारूदी, सुरंगों का जखीरा दबा होगा, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सरकार इनसे छुटकारा के लिए विशेष अभियान चलाये, यह सुरंगे न सिर्फ सुरक्षा बलों, आम आदिवासी के लिए भी घातक है। बस्तर में शांति बहाली और सुरक्षित वातावरण तैयार करने की ठोस कार्य योजना बनाई जाए।



सुशासन त्योंहार, विफलता से ध्यान भटकाने का तरीका: शुक्ला

रायपुर। साल भर काम नहीं होता, अब सुशासन त्योंहार मना कर आवेदन लेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सुशासन का दंभ भरने वाली साय सरकार के राज में आम आदमी छोटे-छोटे काम के लिये सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर है। पटवारी कार्यालय से लेकर तहसील दफ्तरों में लोगों के नामांतरण, फौती, जूटि सुधार के लाखों आवेदन लंबित है, लोगों के काम नहीं हो रहे, आम आदमी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने को मजबूर है। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि लाखों लोगों को सरकार के पास सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे रोजमर्रा के कामों के लिये आवेदन देने सरकार के सुशासन तिहार का इंतजार करना पड़ता है। साय सरकार लोगों के मूलभूत काम को भी नहीं कर पा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार किस बात का सुशासन त्योंहार मनाये जा रही? यदि सरकार में सुशासन होता तो लोगों का काम नियमित हो रहा होता तो त्योंहार मनाये की जरूरत क्यों पड़ती? यह सुशासन त्योंहार अपनी विफलता से ध्यान भटकाने का तरीका है। पिछले बार भी सुशासन त्योंहार मनाये थे और जनता से जो लाखों आवेदन प्राप्त हुए उसको कचरे के ढेर में फेंक दिए।



भाजपा सरकार में महिलायें एवं बेटियां सुरक्षित नहीं: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार में महिलायें एवं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। प्रतिदिन 34 महिलायें एवं 20 बेटियां गायब हो रही हैं, ये सब लचर कानून व्यवस्था के कारण हो रहा है। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा महिलाओं एवं बेटियों की रक्षा करने में असफल हो गये है। बोते दो वर्ष में 2024 में 11,928 एवं 2025 में 12,888 महिलायें, 2024 में 6,935 एवं 2025 में 7,959 बेटियां गायब हुई है। भाजपा का बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ सिर्फ चुनावी जुमला है। रायपुर जिला में 2,100 से अधिक महिलायें एवं बेटियां गायब है जो अब तक मिला नहीं है। 2026 में 31 जनवरी तक 383 बेटियां गायब हो चुकी है। ये भाजपा सरकार की बेटे बचाओ के दावों की पोल खोलती है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में जंगलराज है, मानव तस्करी, अपहरण की घटनायें तेजी से बढ़ी है। महिलाओं एवं बेटियों के साथ हिंसक घटनायें, रेप, गैंगरेप, छेड़छाड़, लूट की घटनायें बढ़ी है, महिला वर्ग डरी हुई है। सरकार महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने में विफल रही है। सरकार की महिला सुरक्षा की दावे हवाहवाई विज्ञापन बाजी तक सीमित है।



बिजली कटौती आम जनता के लिए सरदर्द बन गयी: सिंह

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में अधोषिप्त बिजली कटौती हो रही है। ढाई साल में विद्युत सरफलस वाला छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कटौती का केंद्र बन गया है। गर्मी के मौसम में अधोषिप्त बिजली की कटौती आम आदमी के लिये सरदर्द बन गयी है। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब बिजली दो-चार घंटे के लिये बंद न हो, रात में तो बिजली की स्थिति तो और भयावह हो जाती है, घंटो बिजली गोल हो जाती है। भाजपा से न सरकार संभल पा रहा और न ही व्यवस्थायें। सरकार एक तो पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही, ऊपर से उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का बोझ डाल रही है। प्रदेश के अनेक जिलों में तो पूरी रात बिजली कटौती हो रही है। भाजपा सरकार में आम जनता को मांग के अनुसार बिजली नहीं मिल रहा है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से शहर और गांव की जनता जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान 24 घंटा बिजली की आपूर्ति होती थी। गर्मी के दिनों में मांग बढ़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली की प्रश्रीदी किया जाता था और आम जनता को 24 घंटा बिजली की आपूर्ति की जाती थी।



नक्सलमुक्त का दावा झूठा, सरकार जवाब दे : अभिषेक

रायपुर। कांकेर-नारायणपुर बॉर्डर पर हुए दर्दनाक आईईडी ब्लास्ट में 4 जवानों की शहादत पर आम आदमी पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने इस घटना को नक्सलियों की कायराना हरकत बताते हुए कहा कि यह केवल सुरक्षा बलों पर हमला नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती है। अभिषेक मिश्रा ने कहा कि जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, लेकिन बार-बार इस तरह की घटनाएं यह साबित करती हैं कि सरकार की नक्सल नीति और जमीनी रणनीति में गंभीर खामियां हैं। केवल बड़े-बड़े दावे और आंकड़ों के सहारे नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि जब क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, तो नक्सलियों द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में दूधधूत प्लॉट करना सुरक्षा चुक को दर्शाता है। आखिर खुफिया तंत्र कहाँ था? जवानों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक और संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? अभिषेक मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार को अब केवल बयानबाजी छोड़कर ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की दुःखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।



ब्रह्माकुमारीज समर कैम्प का दूसरा दिन

बच्चों ने जाना स्वस्थ जीवन जीने का तरीका

- **अच्छे स्वास्थ्य से होगा व्यक्ति विकास: डॉ. विवेक भारती**
- **राजयोग से शान्ति, खुशी और बढ़ा हुआ आत्म विश्वास मिलता है: ब्रह्माकुमारी सौम्या दीदी**



रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा चौबे कालोनी में आयोजित समर कैम्प में जाने-माने नैचुरोपैथ डॉ. विवेक भारती ने बच्चों को स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने का तरीका बतलाया। डॉ. विवेक भारती ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक

व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद भोजन और पर्याप्त नींद आदि तीन चीजों का जीवन में होना आवश्यक है। हमारा अच्छा स्वास्थ्य पचास प्रतिशत व्यायाम पर, पच्चीस प्रतिशत भोजन पर और शेष पच्चीस प्रतिशत नींद पर निर्भर करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में

सुधार करने की जरूरत है। योग करने, मनपसंद संगीत सुनने, खेलने और व्यायाम से हमारे अन्दर एण्डॉर्फिन नामक हार्मोन पैदा होता है जो कि हमें खुशी प्रदान करते हैं।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यप्रद आहार में पचास प्रतिशत हिस्सा हरी सब्जियों का हो, पच्चीस

प्रतिशत प्रोटीन और पच्चीस प्रतिशत अनाज को शामिल करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए पांच बातों का ध्यान रखें। पहला दिन में दो बार ही पका हुआ भोजन करें। दूसरी बात दिन में कम से कम ढाई लीटर पानी अवश्य पीएं। तीसरी बात रोज व्यायाम करें। चौथी बात पाचन

तंत्र को आराम देना। इसके लिए सप्ताह में एक दिन उपवास कर लें। पांचवी और प्रमुख बात प्रतिदिन राजयोग मेडिटेशन करें। इससे पहले के सत्र में ब्रह्माकुमारी सौम्या दीदी ने बताया कि राजयोग मेडिटेशन हमारे जीवन में शान्ति, खुशी और आन्तरिक शक्ति को बढ़ाता है। हम राजयोग मेडिटेशन में मन और बुद्धि को परमात्मा में एकजुट करते हैं। आज की तेज और व्यस्त जीवनशैली में लंबे समय तक मेडिटेशन करना हर किसी के लिए संभव नहीं होता इसलिए इस सत्र में एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका बताया गया कि हर घंटे केवल एक मिनट का मेडिटेशन करें।



रायपुर। करीब 106 की आबादी वाले इस छोटे से गांव में कलेक्टर का जमीन पर बैठकर संवाद करना प्रशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक बना। नियद नैखनार योजना 2.0, बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार के तहत आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखीं। कलेक्टर ने मौके पर ही कई

समस्याओं का समाधान कर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सुशासन तिहार के तहत प्रशासन की पहल अब सुदूर वनांचल क्षेत्रों में भी असर दिखा रही है। सुकमा जिले के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पुसगुड़ा में कलेक्टर अमित कुमार ने महुआ पेड़ की छंव में ग्रामीणों के साथ बैठकर जनचौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनीं।

बढ़ा विश्वास

जनचौपाल के दौरान खराब हैंडपंप की शिकायत मिलते ही उसे तुरंत ठीक कराया गया। इसके अलावा गांव में आवश्यक सामुदायिक कार्यों के लिए 20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा।

ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे सुशासन की सच्ची तस्वीर बताया। जनचौपाल के दौरान गांव की मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए पक्की सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव तत्काल मंोग्या गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए गांव को तूफान सवारी वाहन देने की घोषणा की गई।